A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 14 मई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 251, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

विपक्षी इंडिया गठबंधन, मोदी-शाह की जोड़ी से कैसे मुकाबला करेगा?

अरविंद मोहन

चुनाव जीतने और लड़ने के तौर-तरीक़ों की शिकायत अपनी जगह है लेकिन बीजेपी ने हाल में सम्पन्न पाँच राज्यों के चुनाव में जैसा प्रदर्शन किया है उसे कांग्रेस के प्रदर्शन से कोई बहुत ऊपर नहीं माना जा सकता है। लेकिन आज बीजेपी और खासतौर से उसकी मोदी शाह की जोड़ी को इस बार के चुनाव से जो राजनैतिक लाभ हुआ है, उसने इस जोड़ी के साथ ही बीजेपी के ग्राफ़ को अब तक के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस पहले से ज़्यादा अलग-थलग पड़ी है तो इंडिया गठबंधन तो छिन्न-भिन्न हो गया है।

अब हिसाब लगाने वाले यह बता रहे हैं कि मोदी शाह को अभी भी कांग्रेस के पुराने दिनों की स्थिति तक पहुँचने की चुनौती है। लेकिन 1967 के बाद कोई पार्टी इतने राज्यों में सरकार में न थी, जितनी आज बीजेपी है या उसके सहयोगी हैं। 1985 में कांग्रेस लोकसभा में 413 स्थान जीत गई थी लेकिन राजनैतिक ताकत से बहुत बलवान न बनी थी। इस बार यह भी हुआ है कि बीजेपी ने नए चुनाव जितवाने वाले अधिकारियों की टोली को भी पुरस्कृत करने में कोई लिहाज नहीं रखा तो हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है। और कांग्रेस केरलम में जीतकर भी नेता चुनने में दंड प्राणायाम कर रही है। असम कांग्रेस का सिरफुटौव्वल बढ़ गया है। और अब ममता के पक्षधर भी उनकी तथा तृणमूल सरकार की गलतियां गिनवाने लगे हैं।

यहाँ असली मुद्दा दो साल से भी कम अवधि में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनैतिक वापसी और सर्वोच्चता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी जोड़ी की अगुवाई में उतरी थी और चार सौ पार का नारा दिया था। लेकिन परिणाम आने पर यह जोड़ी मुँह छुपाये रही और उसने चालाकी से बीजेपी संसदीय दल में नरेंद्र मोदी को नेता चुनवाने की जगह एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाकर यह औपचारिकता पूरी कराई थी। उसे लग रहा था कि भाजपा की अलग बैठक हुई तो चुनाव प्रदर्शन पर सवाल आएंगे और जवाब देने में मुश्किल आएगी। बल्कि सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन ही नहीं बिगड़ा था योगी बनाम अमित शाह की लड़ाई भी ऐसी स्थिति में आ गई थी कि दोनों के लोग एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने में जुटे थे और प्रधानमंत्री की जीत का अंतर काफी कम हो गया था।

मोदी-शाह की इस जोड़ी ने पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति चालाकी से संभाली और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी साथ लाने में सफलता पाई। चंद्रबाबू विकास परियोजनाएं पाकर खुश रहने वाले थे तो उनके साथ अभी तक ऐसा ही व्यवहार रखा गया है जबकि पहले उनको भाजपा विरोध के चलते जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। नीतीश कुमार को मैनेज करने और ठिकाने लगाने का काम तो उससे भी ज़्यादा कुशलता से हुआ। और आज इस जोड़ी का प्रताप जितना बंगाल जीतने से बढ़ा है, उतना ही बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनवा लेने से भी बढ़ा है।

योगी की चुनौती को सीधे निपटाने का कोई बाहरी प्रयास नहीं दिखा है लेकिन आज योगी की ताकत लोकसभा वाली स्थिति की नहीं है। ऐसा उनकी सत्ता में गिरावट से नहीं हुआ है, शाह और मोदी की ताकत बढ़ने से हुआ है। और पार्टी के अंदर नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे लोग अब गलती से भी कोई बागी स्वर नहीं उठाते। सबसे बड़ा फर्क नितिन नवीन जैसे व्यक्ति को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संघ को उसकी औकात में रहने का संदेश देकर हुआ है। यह शुरुआत जेपी नड्डा ने ही कर दी थी लेकिन फाइनल तो अमित शाह और मोदी ने ही किया है।

दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद बम बम कर रहे विपक्ष की तरफ़ से अब यह फुसफुसाहट भी नहीं आती कि अब मोदी सरकार गिरने वाली है। अब जदयू या तेलगु देशम पार्टी के कभी साथ छोड़ने की कल्पना भी दूर हो गई है। जदयू तो कभी भी भाजपा में समा सकती है। इसमें मोदी शाह की चालाकियों से ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार चुनाव में मिली पराजय का हाथ है।

कई जगह साफ़ दिखती विपक्षी जीत भी हार में बदली और इसमें मोदी शाह के प्रबंध कौशल से ज्यादा विपक्षी कुप्रबंधन का हाथ रहा। और दिन ब दिन इंडिया गठबंधन बेमानी और निष्क्रिय होता गया है। जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी थी लेकिन ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल जैसे लोगों ने भी इसे ध्वस्त करने में कम बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। और बंगाल का चुनाव हारते ही सबको दिखने लगा कि इस कमजोर स्थिति में अगर पूरा इंडिया गठबंधन साथ न भी लड़ता और कांग्रेस तृणमूल ही साथ होते तो कहानी कुछ और होती। और हार के बाद एकजुटता की बात सामने आए इससे पहले सिरफुटौव्वल बढ़ गया। तमिलनाडु के परिणामों और सरकार गठन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और अब द्रमुक गठबंधन में रहेगा, यह भी संशय के घेरे में आ गया है। पर वह कुछ कम महत्व की चीज है। असली सवाल उत्तर प्रदेश और पंजाब में एकता का है जहां जल्दी सरकार बदलने के हालात हैं या चुनाव होंगे।

अब मोदी शाह की जोड़ी को हम चाहें तो कुछ नैतिकता जरूर पढ़ा सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए इस सीमा तक के अनैतिक काम करने की ज़रूरत नहीं है जो बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन और असम में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के काम में दिखा। बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव कराना ज़रूरी था लेकिन चुनाव केंद्र सरकार की निगरानी में कराना जरूरी न था। और हजार करोड़ की पेशकश अगर हुमायूं कबीर जैसे अदना नेता को हुई थी तो उसकी जांच और धर पकड़ की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए थे, सिर्फ पवन खेड़ा के पीछे फौज लगाना अनुचित था। पर उनसे ज्यादा सलाह की जरूरत विपक्षी 'नावाबों' और 'महारानियों' को है। अपने अपने तौर तरीके बदलने और मोदी शाह से सीखने, संघ जैसा कोई बड़ा एजेंडा मानकर उसके इर्द गिर्द राजनीति करने और किसी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भी पूछ वाला तंत्र बनाने की जरूरत है। राहुल तो लोगों में जाते हैं, मुद्दे अच्छे से उठाते हैं लेकिन बाकी कांग्रेसी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। और अखिलेश, तेजस्वी और उद्धव ठाकरे जैसे लोग तो चार कदम खुले में चलने से भी बचते हैं। ऐसे में मोदी शाह का मुकाबला असंभव है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1835 करोड़

नरसिंहपुर में बोले सीएम मोहन- कहीं किसी की नजर न लग जाए, माता और बहनों का सम्मान सर्वोपरि

भोपाल/नरसिंहपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करते हुए महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। नरसिंहपुर के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 296 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी और कहा कि नरसिंहपुर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कहीं इसे किसी की नजर न लग जाए। माता और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 महिलाओं के बैंक खातों में 1835 करोड़ 67 लाख रुपये से ज्यादा की अधिकारी

माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे- सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया, जबकि भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है।

मुंगवानी में नया कॉलेज खोलने की घोषणा - मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि मुंगवानी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा, शेर नदी पर 24 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनेगा और नरसिंहपुर स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राशि अंतरण और भूमि-पूजन एवं लोकार्पण समारोह में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए।

बच्चे को गोद में उठाया, लाठी घुमाई

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 296 करोड़ रुपये की लागत वाले 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इनमें पुल निर्माण, अस्पताल, सड़क और सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बच्चियों पर पुष्प वर्षा की, एक बच्चे को गोद में लेकर लाठी भी घुमाई और गौ-पूजन कर विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह और जेपी नड्डा का

आधा हुआ कफिला

● दिल्ली से लेकर राज्यों तक नजर आने लगा असर ,आधी हुईं गाड़ियां

दिल्ली में मंत्री ई-रिक्शा से चले, यूपी में 2 दिन वर्कफ्रॉम होम का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी है। उन्होंने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने बढ़ती ईंधन कीमतों को देखते हुए पेट्रोल-डीजल बचत की अपील की थी। इससे पहले पीएम मोदी ने भी हाल ही में गुजरात और असम दौरे पर अपने काफिले को छोटा रखा था और केवल जरूरी गाड़ियों को शामिल किया था।

- **यूपी :सांसद-विधायक एक दिन बस-मेट्रो से चलेंगे, 2 दिन वर्कफ्रॉम होम-** देश में ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी में योगी सरकार ने मंगलवार को 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50 फीसदी घटेगा।
हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस-मेट्रो से चलना होगा। सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। राज्य सचिवालय की भी 50 फीसदी बैठकें वर्चुअल होंगी। सीएम ने कहा, जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उन्हें हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। सीएम योगी ने लोगों से 10 अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। पेट्रोल-डीजल और बिजली बचाएं। सजावटी लाइटें कम जलाई जाएं।
- **महाराष्ट्र : मंत्री फ्रांस नहीं जाएंगे, विभाग के खर्च कम किए-** महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने कहा वे इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगे। शेलार ने कहा- चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए विभागीय खर्च में संयम बरतने का फैसला लिया गया है।

शरद की सुबह

मेरी पृथ्वी
कभी उदास नहीं होती
गीत गाती रहती है

मेरी पृथ्वी
हर प्राण को
रसाविल करती रहती है

मेरी पृथ्वी
अपनी माटी की सुगंध से
हर जीवन को
सुगंधित करती रहती है

मेरी पृथ्वी
हर देह को
नये नये रूप देती रहती है

मेरी पृथ्वी
हर कष्ट को झेलकर भी
कभी क्रुद्ध नहीं होती

मेरी पृथ्वी
देवी-रूपा है।

- दुर्गाप्रसाद झाला

एसडीएम के टेबल पर बच्चे ने रख दी चार चॉकलेट

कहा- ले देकर ही सही, सीवर का लीकेज ठीक करवा दीजिए

मुरैना (नप्र)। सरकारी विभागों में काम करने के बदले में रिश्वत लेने के कई मामले सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि अब लोग समझ चुके हैं कि बिना रिश्वत के सरकारी अमला काम नहीं करता है। यह बात बड़े लोगों के साथ-साथ अब बच्चों के दिमाग में भी घर कर गई है कि बिना रिश्वत के सरकारी अमला काम नहीं करता है। यही वजह है कि मुरैना में एक बच्चे को अपने घर के बाहर लीकेज हो रही सीवर को ठीक करवाने के लिए अधिकारी के टेबल पर चार चॉकलेट रख दी।

सीवर ठीक करवाने के लिए रख दिए चॉकलेट- हैरान कर देने वाला यह मामला मुरैना से निकलकर सामने आया है। दरअसल, मुरैना शहर की संजय कॉलोनी में रहने वाले कक्षा 6 के छात्र मानवेंद्र सिंह के घर के बाहर लंबे समय से सीवर का पानी लीकेज हो रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद इस परेशानी को हल नहीं किया गया है।

- **एसडीएम के टेबल पर रख दी चॉकलेट-** यहां पर जनसुनवाई में एडीएम कमलेश भार्गव बैठे हुए थे। मानवेंद्र ने चारों चॉकलेट एडीएम की टेबल पर रख दी और उनसे गुजारिश की कि उसके घर के सामने बह रही सीवर के लीकेज को बंद कर दिया जाए। क्योंकि इस वजह से वह न तो घर के बाहर खेल पा रहा है, न स्कूल जा पा रहा है। हालांकि मासूम की बात सुनकर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
- **काम के बदले चॉकलेट दे दी-** इस बारे में जब मानवेंद्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिना लेनदेन के कोई काम नहीं होता है। इसलिए उन्होंने चार चॉकलेट खरीद कर अधिकारी को दी है और अगर उनका काम नहीं हुआ तो वह यह चारों चॉकलेट वापस ले जाएगा।
- **हर दिन लोकायुक्त की हो रही है कार्रवाई-** गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हर दिन रिश्वतखोर अफसरों पर लोकायुक्त कार्रवाई करती है। इसकी खबरें भी आती हैं। शायद यही वजह है कि मानवेंद्र भी इस बात को पक्का मान बैठा और अधिकारी से काम करवाने के बदले लेनदेन करते हुए उन्हें चार चॉकलेट थमा दी।

अमूल दूध 2 रुपए लीटर महंगा हुआ

आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी 2 लीटर रेट बढ़ाए, नए दाम आज से लागू होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बुधवार को दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की है। दोनों कंपनी के नए दाम गुरुवार (14 मई) से लागू होंगे। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के प्रमुख वेरिएंट और पैक पर कीमतें बढ़ाई हैं। गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक, पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। अमूल का कहना है कि यह बढ़ोतरी 2.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत के बीच है। मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं।

मई 2025 में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे दाम-इससे पहले 1 मई 2025 को गुजरात और अन्य राज्यों में सभी प्रकार के अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इससे पहले 4 जून 2024 को भी सभी वेरिएंट के दाम बढ़ाए गए थे।

हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं

घर में दीया जलाना भी काफी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या खास पूजा-पाठ जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घर में दीया जलाना भी आस्था दिखाने के लिए पर्याप्त है। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने की। बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव, सबरीमाला मंदिर और दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता मामलों पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुनवाई का यह 15वां दिन है। बेंच में जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंद्रेश,अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं।

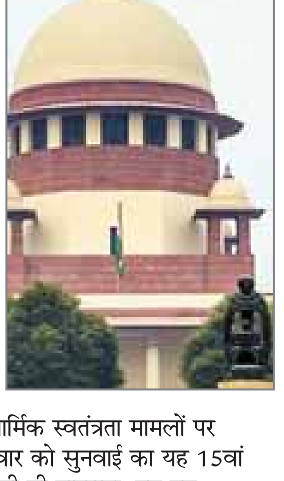

व्यक्ति अपनी आस्था को लेकर स्वतंत्र

सुनवाई के दौरान इंटरविनर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. जी मोहन गोपाल ने कहा कि धार्मिक समुदायों के भीतर से ही सामाजिक न्याय की मांग उठ रही है। उन्होंने 1966 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि तब हिंदू उसे माना गया था, जो वेदों को सर्वोच्च मानता है। उन्होंने कहा, हममें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि हर हिंदू वेदों को सर्वोच्च मानता है। मैं वेदों का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आज हर हिंदू ऐसा मानता है। इस पर जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा, इसी वजह से हिंदू धर्म को जीवन जीने का तरीका कहा जाता है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे
भोपाल ■ गुरुवार, 14 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

रतलाम में 30 मजदूरों से भरा ओवरलोड ऑटो पलटा

15 वर्षीय किशोरी की दबने से मौत, 6 घायल; दो दिन पहले ही कटा था चालान

रतलाम (नप्र)। रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र स्थित सकरावदा में बुधवार सुबह 7:30 बजे एक ओवरलोड ऑटो पलटने से 15 वर्षीय बालिका की दबकर मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऑटो में क्षमता से अधिक करीब 25 से 30 मजदूर सवार थे। तेज गति और ओवरलोड होने के कारण मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ।

जानकारी के अनुसार, ऑटो रिक्शा बुधवार सुबह ग्राम फूफीरुंडी से मजदूरों को लेकर सकरावदा होते हुए सैलाना जा रहा था। सुबह करीब साढ़े सात बजे ऑटो सकरावदा के इमली चौक के पास, पूर्व सरपंच वागजी खराड़ी के घर के सामने एक मोड़ पर पहुंचा। गति अधिक होने और क्षमता से ज्यादा वजन होने के कारण चालक स्टेयरिंग से अपना नियंत्रण खो बैठा और ऑटो पलट गया।

ग्रामीणों ने घायलों को निकाला, किशोरी ने तोड़ा दम- हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर दौड़े और ऑटो में फंसे घायलों को बाहर निकाला। हादसे में फूफीरुंडी निवासी 15 वर्षीय कविता (पिता सूरज खराड़ी) की ऑटो के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सैलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

मिल्क मैजिक ब्रांड में मिलावट का खुलासा

पाम ऑयल और अन्य मिलावटी वस्तुओं के साथ तैयार करते थे प्रोडक्ट, शिकायत दर्ज

भोपाल (नप्र)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़े करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भोपाल स्थित जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक किशन मोदी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत विशेष पीएमएलए कोर्ट में दायर की है। यह शिकायत 11 मई को पेश की गई, जिस पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संज्ञान भी ले लिया है। ईडी के अनुसार कंपनी मिल्क मैजिक ब्रांड नाम से डेयरी उत्पादों का कारोबार करती थी। जांच में सामने आया कि कंपनी दूध की वसा के स्थान पर पाम ऑयल और अन्य पदार्थों की मिलावट कर डेयरी उत्पाद तैयार कर रही थी। इन उत्पादों की बिक्री घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी की गई।

निर्यात के लिए नकली रिपोर्ट तैयार की- जांच एजेंसी ने बताया कि निर्यात की मंजूरी हासिल करने के लिए कंपनी ने प्रतिष्ठित लैब्स की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट्स जमा की थीं। संबंधित प्रयोगशालाओं से सत्यापन कराने पर कई रिपोर्ट्स नकली पाई गईं। ईडी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी ने मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्यात कर करीब 19.69 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। ईडी ने कहा कि यह राशि कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से संचालित की गई, जिसे पीएमएलए के तहत अपराध की आय माना गया है।

संक्षिप्त समाचार

एन. रंगासामी ने 5वीं बार संभाली पुडुचेरी की कमान

- एनडीए सरकार ने यहां फिर दोहराया सत्ता का इतिहास

पुडुचेरी (एजेंसी)। पुडुचेरी के दिग्गद नेता एन रंगासामी ने बुधवार को लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक रंगासामी ने एक बार फिर एनडीए सरकार का नेतृत्व संभाल लिया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में

उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रंगासामी ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। उनके साथ मल्लादी कृष्णा राव और भाजपा नेताअरुमुगम नमस्सिवयम ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। खास बात यह रही कि मल्लाडी कृष्णा राव ने तेलुगु भाषा में शपथ ली। वह पुडुचेरी के यानम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश के भीतर स्थित है।

तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में हो गई पास

- एआईएडीएमके के 47 में से 25 बागी विधायकों ने समर्थन किया

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा में विजय सरकार ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। सदन में वोटिंग के वक्त 172 विधायक मौजूद रहे। टीवीके के समर्थन में 144 वोट पड़े। 234 सदस्यीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। विजय

त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर से सीटें जीते थे। सीएम बनने के बाद पेरम्बूर से इस्तीफा दे दिया। तिरुपत्तूर के विधायक श्रीनिवासा सेतुपति एक वोट से जीते थे। मामला मद्रास हाईकोर्ट में होने की वजह से उन्हें वोट डालने के लिए मंजूरी नहीं मिली। इस तरह सदन में विधायकों की संख्या 232 रह गई। टीवीके को 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक के अलावा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), वीसीके और आईएमएलयू से बागी विधायक ने समर्थन किया। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 22 वोट पड़े, जो एआईएडीएमके के बचे हुए विधायकों के रहे।

अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक का निधन

- पोस्टमॉर्टम के बाद शव घर लाया गया, अपर्णा भी पहुंचीं

लखनऊ (एजेंसी)। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल

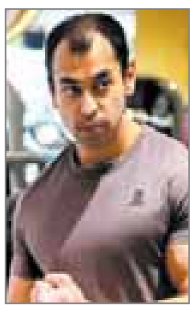

अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. डीसी पांडेय के मुताबिक, जब प्रतीक को लाया गया, तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी। हार्ट भी रुक चुका था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। सूत्रों के मुताबिक, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि, मौत की वजह स्पष्ट न होने के कारण विसरा सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद प्रतीक का शव घर ले आया गया है। यहां अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच, प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव भी असम से लखनऊ लौट आई हैं। वो एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंचीं।

मप्र में शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा

सुप्रीम कोर्ट बोला- बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता, जो छूट मिलनी थी, मिल चुकी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में जो भी छूट दी जानी थी, वह पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में अब होने वाली किसी भी भर्ती में पात्रता परीक्षा पास किए बिना कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार के साथ मध्य प्रदेश और देशभर के अन्य राज्यों के शिक्षा संगठनों की ओर से दायर की गई थी। याचिकाओं में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी।

पांच साल की छूट पहले ही दी जा चुकी- हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2017 में नियम लागू होने के बाद पांच साल की छूट पहले ही दी जा चुकी है। सुप्रीम

कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा तय किए गए नियमों का पालन सभी राज्यों और शिक्षकों को करना होगा।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और अधिवक्ताओं की ओर से विभिन्न दलीलें पेश की गईं, लेकिन फिलहाल शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है।

हालांकि, 70 से अधिक याचिकाओं पर बुधवार शाम तक सुनवाई जारी रही। ऐसे में मामले में अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है।

कोर्ट का रुख सकारात्मक नहीं लगा- शिक्षक संघ

जनजातीय कल्याण शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगौर ने कहा- हमारे संगठन ने भी एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान वह खुद मौजूद थे। अधिवक्ताओं के मजबूत तर्कों के बावजूद कोर्ट का रुख सकारात्मक नहीं लगा। दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 1998 से 2009 के बीच बिना टीईटी नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए थे। ये नियुक्तियां राज्य सरकार की मेरिट प्रक्रिया के तहत हुई थीं। मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब डेढ़ लाख बताई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- परीक्षा में फेल हुए तो नौकरी जा सकती है- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि यदि कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करता है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी होने पर प्रदेशभर के शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। शिक्षक संगठनों ने फैसले के खिलाफ आंदोलन भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार की मांग की।

चार सप्ताह पहले ही मिल जाएगी वेदर रिपोर्ट

- मौसम विभाग ने लॉन्च की एआई आधारित दो नई सर्विस

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को दो नई सेवाएं शुरू कीं। इनमें एक एआई-सक्षम मानसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली है, जो 16 राज्यों और 3,000 से अधिक उप-जिलों के किसानों की मदद के लिए मौसमी बारिश की प्रगति और स्थानीय मौसम की जानकारी चार सप्ताह पहले

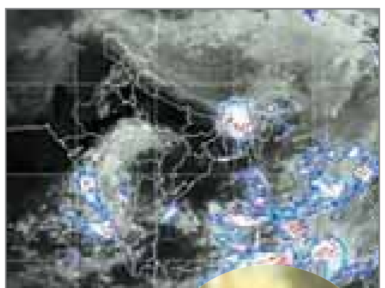

तक उपलब्ध कराएगी। दूसरे प्रोडक्ट को एक पायलट सर्विस के तौर पर शुरू किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के लिए हाई-रिजॉल्यूशन वाला स्थानीय बारिश का पूर्वानुमान लगाएगा। यह घने ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क और एआइ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1 किमी. रिजॉल्यूशन पर 10 दिन पहले तक बारिश का ऑपरेशनल पूर्वानुमान तैयार कर सकता है। ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लगातार विस्तार के साथ ऐसी ही सेवाएं धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों तक भी बढ़ाई जाएंगी।

भारत और रूस मिलकर निकालेंगे रेयर अर्थ खजाना

- देखता रह जाएगा चीन, जल्द होने वाली है बड़ी डील

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और रूस मिलकर एक बड़ी डील करने वाले हैं। यह डील रेयर अर्थ यानी महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की खोज, उनकी प्रोसेसिंग और तकनीकी सहयोग से जुड़ी होगी।

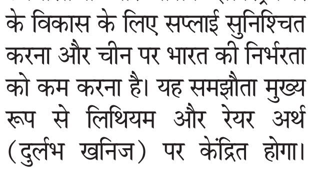

रॉयटर्स के मुताबिक इस डील पर दोनों देश जल्दी ही साइन कर सकते हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सप्लाई सुनिश्चित करना और चीन पर भारत की निर्भरता को कम करना है। यह समझौता मुख्य रूप से लिथियम और रेयर अर्थ (दुर्लभ खनिज) पर केंद्रित होगा। अगले दो महीनों के भीतर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत ने पहले ही प्रस्तावित समझौते का मसौदा रूस के साथ शेयर कर दिया है। वर्तमान में चीन कई महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर हावी है। भारत अपनी ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं के लिए नए विदेशी सोर्स सुरक्षित करना चाहता है। सूत्रों का कहना है कि अगर पश्चिम अफ्रीकी देश माली में राजनीतिक स्थिति स्थिर होती है, तो भारत रूसी सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम के लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में फिर से शामिल होने पर विचार कर सकता है। इससे पहले सुरक्षा कारणों से भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। भारत ने केवल रूस ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के साथ भी खनिज सुरक्षा के लिए गठबंधन किए हैं।

किश्तवाड़ में आतंकी को पनाह देने वाला शिक्षक गिरफ्तार

एक साथी भी पकड़ाया, पुंछ में घुसपैठ की कोशिश में एक आतंकी ढेर

किश्तवाड़/पुंछ (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकारी स्कूल के एक शिक्षक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को पनाह, खाना और दूसरी मदद देने का आरोप है। गिरफ्तार शिक्षक की पहचान मशकूर अहमद के रूप में हुई है। वह इंदरवाल के एक सरकारी स्कूल में तैनात है। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, वह चटरू इलाके में आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। यह मामला 4 फरवरी 2026 को डिच्छर-चटरू में हुए एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसमें आतंकी आदिल मारा गया।

जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें

- पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले-भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल है जमा

45 दिन का एलपीजी स्टॉक भी, पीएम की बातों का मनगढ़ंत मतलब न निकालें

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की एलएनजी और 45 दिन की एलपीजी का स्टॉक है। सप्लाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। हरदीप पुरी ने दिल्ली में आयोजित सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट में पीएम की बचत की अपील का भी जिक्र किया। पुरी ने कहा कि पीएम ने दो दिन पहले जो बातें कही हैं। उसको लेकर अफरा-तफरी मचाना बेकार है। पीएम की बातों को ध्यान से सुनें। उसका मनगढ़ंत मतलब न निकालें। दरअसल पीएम मोदी लगातार दो दिन लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। विदेशी यात्राओं से बचें। हरदीप पुरी ने समिट में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा सप्लाई में आई रुकावटों को बोझ आम जनता पर पड़ने नहीं दिया है। तेल कंपनियों को हर दिन 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो घाटा 1,98,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। अगर आप तिमाही के आंकड़ों को देखें तो कुल नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में, आप इसे

कब तक इसी तरह बनाए रख सकते हैं। तेल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। पहले यह लगभग 64 या 65 के आसपास हुआ करती थीं।

- बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने लागू कर दिया मोदी का फॉर्मूला

वर्क फ्रॉम होम! इलेक्ट्रिक गाड़ी मंत्रियों को भी नसीहत

पटना (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद देश भर के राजनीतिक नेताओं और सरकारों ने ईंधन बचाने के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई नेताओं ने ईंधन बचाने और ऊर्जा बचत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो यात्रा, इलेक्ट्रिक वाहनों और काफिले का आकार घटाने जैसे विकल्पों को चुना। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

- **मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम-** मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है। जनप्रतिनिधि गण से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने की अपील की गई है।

- बंगाल सीएम सुवेंदु ने नंदीग्राम सीट छोड़ी

भवानीपुर पास रखेंगे

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पास रखी और नंदीग्राम सीट छोड़ने का फैसला किया। सुवेंदु ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराया है।

शपथ लेने के बाद सुवेंदु ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। इसमें निर्देश दिया कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं होगा। नियम नहीं मानने पर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

- **महिला सुरक्षा पर भी दिए निर्देश-** सरकार ने महिला सुरक्षा और राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा, गुंडागर्दी व रंगदारी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध, खासकर 2021 और 2024 के चुनाव के बाद दर्ज हुए रेप, रेप के प्रयास और छेड़छाड़ के मामलों को दोबारा खोला जाएगा। जरूरत पड़ने पर 2021 की हिंसा की उन शिकायतों की फिर से जांच होगी, जो केवल जनरल डायरी में दर्ज की गई थीं।

रिटायर्ड जज की प्रेग्नेंट बहू ने दी जान

पांच महीने पहले भोपाल में हुई थी शादी, मृतक के परिवार ने लगाया बड़ा आरोप

भोपाल (नप्र)। कटारा हिल्स इलाके में रिटायर्ड जज की प्रेग्नेंट बहू ने जान दी है। मृतक महिला का पोस्टमार्टम एम्स में करवाया गया है। वहीं, मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। मृतक महिला का नाम ट्विशा शर्मा है। वह नोएडा की रहने वाली थी। मंगलवार की रात महिला ने अपनी मां से बात की थी, जिसमें परेशानी का जिक्र किया था।

सामर्थ से हुई थी शादी

वहीं, ट्विशा के कदम से मायके पक्ष के लोग हैरान हैं। उनका कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है। बताया जा रहा है कि महिला की सास रिटायर्ड जज हैं। ट्विशा और सामर्थ की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी। पांच महीने बाद ही उसने ससुराल में यह कदम उठाया है।
पति पर अपमानित करने का आरोप– दरअसल, मृतक ट्विशा का भाई इंडियन आर्मी में मेजर हैं। उसने अपने घरवालों को फोन कर बताया था कि पति मुझे कुछ दिनों से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। हर छोटी बात पर मुझे अपमानित करते हैं। मुझे नोएडा आना है। परिवार ने नोएडा वापस लौटने के लिए रिजर्वेशन करवा दिया था। लेकिन उससे पहले मौत की खबर आई।
परिवार ने लगाया हत्या का आरोप– वहीं, ट्विशा की चाची जलपा शर्मा ने मीडिया से फोन पर बातचीत में कहा कि हमारे परिवार को बताया गया है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन हमें विश्वास नहीं है। परेशानी की हालत में भी उसने अपनी मां से कहा था कि मम्मी आप डरना नहीं, मैं परेशानी की हालत में भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, जिससे आपलोगों का नाम खराब हो। अचानक से ऐसा क्या हुआ, उसके गले पर नाखून और रस्सियों के निशान हैं। कान नीले पड़ गए हैं। ट्विशा के पति ड्रग एडिक्ट थे, हमारी ट्विशा को भी ड्रग एडिक्ट बनाने पर तुले थे। वह केस को उल्टा करना चाह रहे हैं।

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट

भोपाल रीजन के 79.43 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास

लड़कियों ने फिर बाजी मारी; एमपी में 12.14 प्रतिशत छात्र सभी विषयों में फेल

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार दोपहर 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। भोपाल के 9,399 समेत मध्य प्रदेश के 80,454 छात्रों के साथ देशभर के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया। इस बार भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कमजोर रहा।
भोपाल रीजन में 79.43 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, जबकि देशभर का औसत पास प्रतिशत 85.20 प्रतिशत दर्ज किया गया, यानी भोपाल रीजन राष्ट्रीय औसत से 5.77 प्रतिशत पीछे रहा। भोपाल का प्रदर्शन रायपुर, लखनऊ और रांची जैसे कई रीजन से भी कमजोर रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम

देशभर में इस वर्ष 12वीं का कुल पास प्रतिशत 85.20 रहा, जो पिछले वर्ष के 88.39 प्रतिशत की तुलना में 3.19 प्रतिशत कम है। क्षेत्रवार प्रदर्शन में तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) सबसे बेहतर रहा, जहां 95.62 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए।

युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

- पत्नी मायके से नहीं लौट रही थी, इसे लेकर डिप्रेशन में था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रहने वाले युवक का शव आज सुबह करीब 6 बजे उसके घर के एक कमरे में लटका दिखा। बॉडी को सबसे पहले उसकी मां ने देखा था। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी अपने मायके में रह रही है। कई बार मनाने के बाद भी वह लौटने को तैयार नहीं थी। इससे डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पांच साल पहले हुई थी शादी

छोला मंदिर पुलिस ने बताया कि प्रदीप लोवंशी पिता गंगाराम लोवंशी (29) शिव नगर बिहारी कॉलोनी सुबह साढ़े चार बजे टाविल से फांसी लगाई है। मां ने सबसे पहले देखा था। पांच साल पहले शादी हुई थी। शादी के दो महीने बाद पत्नी मायके में चली गई थी। फिर दोबारा नहीं लौटी। इसी बात को लेकर युवक डिप्रेशन में रहता था और शराब पीने का आदि हो चुका था।

मध्यप्रदेश में जानलेवा गर्मी

75 साल का रिकॉर्ड टूट गया

● 11 जिलों में 4 दिन लू का अलर्ट ● पांढुर्णा में बारिश, सिवनी में ओले भी गिरे, भोपाल, इंदौर-शाजापुर में तेज धूप

● रतलाम में 46.5 डिग्री पारा, मौसम विभाग ने दिया भीषण लू और बार्म नाइट अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। रतलाम में 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिन का तापमान 46.5 डिग्री तक उछल गया। यहां प्रदेश में सबसे अधिक है। लगभग पूरे प्रदेश में तापमान 40 से 46 डिग्री के बीच है। मौसम विभाग ने आगामी एक हफ्ते में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी, हीटवेव और बॉर्म नाईट का ऑरेंज-यलो अलर्ट दिया है। बुधवार को सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में ओले भी गिरे। पांढुर्णा में भी शाम को पानी गिरा। भोपाल में सुबह बादल छाए रहे। फिर तेज धूप निकली। रतलाम और आगर-मालवा में बादलों की वजह से उमस बनी रही। वहीं, बालाघाट में काले बादल छाए रहे। हवा चलने से तपन से लोगों को हल्की राहत मिली। शाजापुर में तपिश बरकरार रही।

मौसम विभाग के मुताबिक, इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले अगले 4 दिन तक लू की चपेट में रहेंगे। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलेगी। विभाग ने सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। पांढुर्णा, बैतूल, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, जबलपुर, देवास, सतना, रायसेन, सागर और दमोह में भी मौसम बदला रह सकता है।

एमपी के इन शहरों में भीषण लू का यलो और ऑरेंज अलर्ट– आईएमडी ने मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भीषण लू और गर्म रात्रि का अलर्ट जारी किया है। यलो अलर्ट वाले शहरों में राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास, शाजापुर, आगर शामिल हैं। वहीं रतलाम में तीव्र उष्ण लहर अर्थात भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसी प्रकार धार, इंदौर और उज्जैन में भी तेज लू का प्रकोप रहेगा। यहां गर्म रात्रि को लेकर भी अलर्ट है।

दूसरे हिस्से में गरज-चमक और बौछारों की संभावना

प्रदेश में मौसम कई महीनों से अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दोहरे रूप दिखा रहा है। इसमें गुरुवार के लिए बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई। शाम के बाद इन इलाकों में गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। बाकी पूरा प्रदेश शुष्क रहेगा।

प्रदेश में अगले 5 दिनों का मौसम का अलर्ट

- 14 मई: रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा में लू का असर
- 15 मई: भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में गर्म हवाएं
- 16 मई: ग्वालियर-चंबल और मालवा क्षेत्र में तेज आंधी और गरज-चमक
- 17 मई: पश्चिमी और उत्तरी एमपी में तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है

रातों को जागे

किसी ने कमरे में काटे महीने

नीट परीक्षा कैंसिल होने से सदमे में छात्र, भोपाल में 19000 ने दिया था एग्जाम

भोपाल (नप्र)। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह समय किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने भोपाल समेत देशभर के छात्रों को गहरे तनाव में डाल दिया है।

छात्रों का टूटा हौसला– भोपाल की एक छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि महीनों की रातों की नींद और मेहनत का परिणाम था। उन्होंने बताया कि जब घर से फोन आया कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। भोपाल में एनएसयूआई ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और जवाबदेही तय करने की मांग की।

कोचिंग और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय

कोचिंग संस्थान चलाने वाले अमित गुप्ता का कहना है कि छात्र दिन में 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। ऐसी घटनाओं से वे डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनमें मानसिक तनाव बढ़ जाता है। वहीं, मनोविज्ञान के प्रोफेसर विनय मिश्रा ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इस वास्तविकता को स्वीकार करें और नई ऊर्जा के साथ दोबारा तैयारी में जुटें। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों पर दबाव बनाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें।

करोंद में बिल्डिंग में आग

केएफसी आउटलेट के पास उठीं आग की लपटें; एसी और फर्नीचर जला

भोपाल (नप्र)। भोपाल के करोंद स्थित एक चार मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में बुधवार को आग लग गई। इस बिल्डिंग में केएफसी आउटलेट है। इसके ठीक पास में लगे एयर कंडिशनर समेत फर्नीचर जल गया। आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। अफरा-तफरी के माहौल के बीच आग पर काबू पाया गया। इससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के दौरान बिल्डिंग में भीड़ नहीं थी। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन नुकसान का आकलन लगा रहा है।

युवक की पिटाई के बाद उबले समाज के लोग

आधी रात को ताजुल मस्जिद के पास प्रदर्शन, धारा-144 लागू

भोपाल (नप्र)। गोविंदपुरा के एक होटल में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा गया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम युवक की पिटाई की थी। साथ ही चेहरे पर गोबर और स्याही पोत दी थी। इसे लेकर आधी रात पुरानी भोपाल के ताजुल मस्जिद के पास हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा हो गए और प्रदर्शन किया है। एहतियात के तौर अभी भी उस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है।

भोपाल को बंद करने की चेतावनी– वहीं, भोपाल शहर के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में चेतावनी दी गई कि यदि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो शहरव्यापी बंद का आह्वान होगा। काजियात परिसर में विरोध-प्रदर्शन करते हुए समुदाय के लोगों ने हमले और घटना के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की निंदा की।

धार्मिक भावनाओं पर है हमला– भीड़ को संबोधित करते हुए काजी नदवी ने इस हमले को न केवल एक व्यक्ति पर हमला, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक भावनाओं पर भी हमला बताया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस नियंत्रण कक्ष की ओर मार्च किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मोहसिन अली के साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

भोपाल पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन– इसके साथ ही समुदाय के प्रतिनिधियों ने भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर घटना के दौरान कथित रूप से लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई की मांग की। शहर काजी ने कहा यह मामला केवल शारीरिक हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग से धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।

भय का माहौल पैदा करती हैं ये घटनाएं– भोपाल शहर काजी ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अपराधियों का साथ दिया। ऐसी घटनाएं भोपाल में भय का माहौल पैदा करती हैं और वातावरण को दूषित करती हैं।

मामले की कर रहे हैं जांच

वहीं, कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के आचरण सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। पुलिस घटना के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कहा कानून के हिसाब से संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की मौजूदगी की जांच की जा रही है।

मध्यप्रदेश में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं!

एनसीआरबी रिपोर्ट में एमपी फिर नंबर-1, आखिर क्यों सॉफ्ट टारगेट बन रहे सीनियर सिटीजन?

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में बुजुर्गों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट के मुताबिक, बीते एक साल में राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के कुल 5,875 मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा और अधिक भयावह होता जा रहा है।

हिंसा और यौन अपराधों का बढ़ता ग्राफ– हैरान करने वाली बात यह है कि ये अपराध केवल छोटी-मोटी चोरी या संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार, एक साल में 144 बुजुर्गों की हत्या हुई है। वहीं, बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। रिपोर्ट में रेप के 23 मामले और छेड़छाड़ के 17 मामले दर्ज किए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोकलाज और डर के कारण वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

डिजिटल अरेस्ट और धोखाधड़ी का नया खतरा– जांचकर्ताओं का कहना है कि अकेलेपन और डिजिटल जानकारी के अभाव के कारण बुजुर्ग अब सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। पेंशन फ्रॉड, संपत्ति कब्जाने और हाल ही में बढ़े डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों ने सीनियर सिटीजंस की नींद उड़ा दी है। पुलिस की विशेष हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग के बावजूद, इन अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है।

परिचित ही निकलते हैं आरोपी

पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की मुख्य वजह उनका सामाजिक अलगाव और शारीरिक कमजोरी है। कई मामलों में अपराधी बाहरी व्यक्ति न होकर परिवार के करीबी या परिचित ही होते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार हेतु) वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी दी कि यह पुरस्कार मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा उनके अधीन कार्यरत निगम, मंडल, बोर्ड एवं संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके नवाचार आधारित उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा।
यह पुरस्कार 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये प्रदान किये जायेंगे। ऐसे कार्य जिनसे प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सेवा प्रदाय व्यवस्था अथवा जनहित में सकारात्मक और प्रभावी परिवर्तन आया हो।
मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत नागरिक सेवा प्रदाय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, अधोसंरचना, सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण, रोजगार एवं आर्थिक विकास जैसे प्रमुख कार्यक्षेत्रों में किए गए नवाचारों को सम्मानित किया जाएगा।

संपादकीय

एनटीए की साख पर सवाल

समूचे देश में एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) द्वारा कुल 407 मेडिकल कॉलेजों की यूजी (स्नातक) कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयोजित नीट 2026 (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट) के पेपर लीक होने के बाद पूरी परीक्षा निरस्त करने से करीब 23 लाख परीक्षार्थियों में मायूसी है। इनमें से ज्यादातर वो हैं, जो डॉक्टरी में अपने सुनहरे भविष्य का सपना तलाशते हुए पूरी मेहनत कर रहे थे। नीट आयोजित करने वाली एनटीए ने पेपर लीक के मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए जहां पूरी परीक्षा रद्द कर दी है, वहीं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आरंभिक जांच में नीट पेपर लीक का एक विशाल देश भर में फैला नेटवर्क सामने आया है। सीबीआई की जांच पूरी होने पर पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार में कई स्तरों पर कई लोग शामिल हैं, इसमें संदेह नहीं। नीट पेपर लीक का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे हैं। इससे जहां परीक्षा आयोजन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, वहीं इस व्यवस्था में लगे लोगों की नैतिक ईमानदारी और ऑन लाइन पेपर सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीट रद्द। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। गौरतलब है कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों की 1 लाख यूजी कक्षा में प्रवेश के लिए बीती 3 मई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के कुछ समय पहले ही कई जगह इसके गैस पेपर वायरल हुए, जो वास्तविक पेपर से काफी मिलते-जुलते थे। ये पेपर कई परीक्षार्थियों ने लाखों रूपए देकर खरीदे थे, बिना यह सोचे कि अगर परीक्षा रद्द हो गई तो उनका यह पैसा पानी में चला जाएगा। उधर पेपर लीक को लेकर एनटीए ने अपने बयान में कहा कि जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह तय हुआ कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखें और नए एडमिट कार्ड का शेड्यूल आने वाले दिनों में एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से जारी किया जाएगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा परीक्षा के पेपर में भी गोपनीयता बरकरार रह पाएगी या नहीं। जहां तक मप्र की बात है तो पेपर लीक मामले के तार इस राज्य से सीहोर से जुड़ रहे हैं, जहां पुलिस ने पेपर लीक मास्टर माइंड शुभम् खैरनार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे नाशिक से गिरफ्तार किया। लेकिन शुभम के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसका खुलासा आगे हो सकता है। उल्लेखनीय है कि एनटीए का काम पहले भी बहुत विश्वसनीय नहीं रहा है। 2024 में भी एजेंसी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब असामान्य रूप से बहुत ज्यादा उम्मीदवारों ने रैंक 1 हासिल की थी। उस समय ग्रेस मार्क्स, बढ़े हुए स्कोर और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए थे। तब भी पेपर लीक और संगठित नकल के आरोप सामने आने के बाद जांच शुरू की गई थी। कई लोगों को राज्य पुलिस एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया था। छात्र, अभिभावक और शिक्षक परीक्षा रद्द कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने माना था कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की 'पवित्रता' प्रभावित हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने एनटीए के कामकाज में सुधार की घोषणा की थी। लेकिन नतीजा सामने है।

चरखे से बाजार तक चमक खोती खादी

प्रभाव खादी की संस्थागत संरचना पर भी पड़ा है। देश भर में सैकड़ों खादी संस्थाएँ दशकों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए थीं। ये संस्थाएँ केवल उत्पादन केंद्र नहीं थीं, बल्कि ग्रामीण समाज के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार थीं। आज इन संस्थाओं की स्थिति चिंताजनक है। कई संस्थाएँ वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। कच्चे माल की लागत बढ़ी है, भुगतान में देरी होती है, और कार्यशील पूंजी का अभाव उत्पादन को सीमित करता है। सरकारी योजनाएँ मौजूद हैं, पर उनकी प्रक्रिया जटिल है।

नजरिया

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

खादी आज फिर चर्चा में है। उपलब्धियों के दावे हैं, बढ़ते कारोबार के आंकड़े हैं, और एक नई चमक भी है। लेकिन इसी चमक के बीच एक असहज प्रश्न लगातार उपस्थित है क्या यह विकास खादी का है या खादी के नाम पर विस्तृत होते बाजार का पिछले वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग के विस्तार को एक बड़ी आर्थिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 24-25 का कुल कारोबार 1.70 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच चुका है। उत्पादन, बिक्री और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि के दावे किए गए हैं। यह तस्वीर प्रभावशाली है। परंतु जब हम इन आंकड़ों की तह में जाते हैं, तो एक अलग यथार्थ सामने आता है।

कुल कारोबार में खादी वस्त्रों की हिस्सेदारी लगभग 7,145 करोड़ रुपये है याने करीब 4 प्रतिशत। शेष 96 प्रतिशत हिस्सा ग्रामोद्योग की अन्य गतिविधियों का है। इसका अर्थ यह है कि जिस रिकॉर्ड वृद्धि की बात की जा रही है, उसका केंद्र खादी कपड़ा नहीं है।यहाँ से प्रश्न उठता है क्या हम खादी की सफलता का उत्सव मना रहे हैं, या ग्रामोद्योग के विस्तार को खादी के नाम से देख रहे हैं?

इस प्रश्न का उत्तर खादी के मूल विचार में छिपा है। महात्मा गांधी के लिए खादी केवल वस्त्र नहीं थी। वह स्वराज का माध्यम थी। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक सच्चा स्वराज संभव नहीं है। गांधी ने खादी को एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा। यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी जहाँ उत्पादन छोटे स्तर पर, स्थानीय संसाधनों और श्रम के आधार पर होता है। चरखा इस व्यवस्था का प्रतीक था। वह केवल धागा नहीं कातता था, बल्कि बेरोजगारी, असमानता और शोषण के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध भी था। खादी का अर्थ था हर हाथ को काम, हर गांव को आत्मनिर्भरता, और हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन।

आज जब हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या खादी अब भी उसी विचार का प्रतिनिधित्व करती है? बाजार में उपलब्ध खादी की स्थिति इस प्रश्न को और तीखा बनाती है। खादी अब सस्ती और सर्वसुलभ नहीं रही है। उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। आम उपभोक्ता के लिए उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। जो वस्त्र कभी किसान और मजदूर की पहचान था, वह अब एक विशेष वर्ग का परिधान बनता दिखता है। यह बदलाव केवल उपभोग का नहीं, बल्कि सामाजिक चरित्र का भी संकेत है।

इसका प्रभाव खादी की संस्थागत संरचना पर भी पड़ा है। देश भर में सैकड़ों खादी संस्थाएँ दशकों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए थीं। ये संस्थाएँ केवल उत्पादन केंद्र नहीं थीं, बल्कि ग्रामीण समाज के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार थीं। आज इन संस्थाओं की स्थिति चिंताजनक है। कई संस्थाएँ वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। कच्चे माल की लागत बढ़ी है, भुगतान में देरी होती है, और कार्यशील पूंजी का अभाव उत्पादन को सीमित करता है। सरकारी योजनाएँ मौजूद हैं, पर उनकी प्रक्रिया जटिल है। समय पर सहायता न मिलने से संस्थाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।

इसके साथ ही बाजार में एक नया वर्ग उभरा है ब्रांडेड और डिज़ाइनर 'खादी' का। यह वर्ग आधुनिक प्रस्तुति, पैकेजिंग और विपणन के माध्यम से खादी को एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित कर रहा है। परंपरागत खादी संस्थाएँ इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है, और वे तेजी से बदलते बाजार के अनुरूप खुद को ढाल नहीं पातीं। इसका सीधा असर कारीगर पर पड़ता है।

आँकड़ों में रोजगार का आंकड़ा लगभग 1.94 करोड़ बताया जाता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि इनमें कितने लोग स्थायी और पूर्णकालिक रोजगार में हैं। बड़ी संख्या असंगठित और अंशकालिक हो सकती है।

कारीगर की आय आज भी अनिश्चित और सीमित है। कई बुनकर और कतिन नियमित और पर्याप्त आय से वंचित हैं। यहीं खादी की सफलता का दावा कमजोर पड़ता है। यदि उत्पादन बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है, पर कारीगर की स्थिति नहीं बदलती, तो यह विकास अधूरा है।

इसी संदर्भ में सूत उत्पादन और चरखों की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। खादी की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत सूत कातने से होती है। चरखा इस व्यवस्था की मूल इकाई है। लेकिन आज कई क्षेत्रों में चरखे या तो कम हो गए हैं या निष्क्रिय पड़े हैं। हाथ से काते सूत की जगह मशीन निर्मित धागे का उपयोग बढ़ रहा है। इससे खादी की मूल पहचान प्रभावित होती है। यदि सूत ही मशीन से आने लगे, तो खादी का वह श्रम-आधारित स्वरूप कमजोर हो जाता है, जो उसे विशिष्ट बनाता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा लगभग 2.87 लाख मशीनें और टूलकिट वितरित किए जाने का दावा भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इन टूलकिटों में मधुमक्खी पालन किट, अगरबत्ती और सुगंधित उत्पाद बनाने की मशीनें, मिट्टी और हस्तशिल्प के उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और अन्य ग्रामीण उद्योगों के औजार शामिल हैं।

यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन खादी से सीधे जुड़े उपकरण जैसे चरखा और करघा इनमें सीमित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास का केंद्र खादी वस्त्र उत्पादन से हटकर व्यापक ग्रामोद्योग की ओर स्थानांतरित हो गया है। एक और गंभीर चुनौती खादी की पहचान को लेकर है। बाजार में 'खादी लुक' और 'हैंडस्पन स्टाइल' जैसे शब्दों के साथ मशीन निर्मित कपड़े बेचे जा रहे हैं। इससे उपभोक्ता भ्रमित होता है और असली खादी को नुकसान होता है। पारंपरिक खादी संस्थाएँ इस दोहरी मार का सामना कर रही हैं एक ओर बाजार की प्रतिस्पर्धा, दूसरी ओर पहचान का संकट।

गांवों में इसका असर साफ दिखाई देता है। कई उत्पादन केंद्र बंद हो चुके हैं या सीमित हो गए हैं। करघों की आवाज धीमी पड़ रही है। नई पीढ़ी इस पेशे में भविष्य नहीं देखती। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैचारिक संकट भी है। खादी की सफलता की असली कसौटी यह नहीं है कि उसका कारोबार कितना बढ़ा। असली कसौटी यह है कि क्या उसने गांवों में स्थायी रोजगार पैदा किया, क्या उसने कारीगर को सम्मानजनक जीवन दिया, और क्या उसने आत्मनिर्भरता के उस विचार को मजबूत किया, जिसकी नींव गांधी ने रखी थी। यदि खादी वस्त्र कुल कारोबार का केवल 4 प्रतिशत हैं, तो यह संकेत है कि खादी का मूल क्षेत्र अभी भी कमजोर है।

इसलिए आवश्यक है कि खादी और ग्रामोद्योग के बीच स्पष्ट अंतर समझा जाए। दोनों का विकास जरूरी है, पर उन्हें एक-दूसरे का पर्याय मानना खादी के विचार के साथ न्याय नहीं करता। नीतिगत स्तर पर खादी संस्थाओं को केंद्र में रखना होगा। वित्तीय सहायता को सरल और समयबद्ध बनाना होगा। पारंपरिक कारीगरों को बाजार से जोड़ने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। असली खादी की पहचान सुनिश्चित करनी होगी, ताकि उपभोक्ता भ्रमित न हो और कारीगर को उसका उचित मूल्य मिल सके। खादी को केवल एक प्रीमियम उत्पाद बनाने के बजाय उसे फिर से जनसामान्य के जीवन से जोड़ना होगा। खादी की कहानी आंकड़ों से नहीं, बल्कि उन हाथों से लिखी जाएगी, जो चरखा चलाते हैं और करघा बुनते हैं। यदि 1.70 लाख करोड़ के कारोबार के बावजूद उन हाथों का जीवन नहीं बदलता, तो यह सफलता अधूरी है। और यदि खादी को सचमुच जीवित रखना है, तो उसे फिर से उसी जमीन पर खड़ा करना होगा, जहाँ से वह उठी थी गांव, कारीगर और आत्मनिर्भरता का विचार। यही खादी की असली कसौटी है।

नई पीढ़ी के सपनों की सामूहिक हत्या

पेपर लीक

सपना सी.पी. साहू

लेखक पत्रकार हैं।

किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस युवा शक्ति को वह अपनी सबसे बड़ी पूंजी और जनसांख्यिकीय लाभांश कहता है, उसी का भविष्य आज पेपर लीक और शिक्षा माफिया के अंधेरे गलियारों में सरेआम नीलाम हो रहा है। नीट जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा का पेपर लीक होना महज एक प्रशासनिक चूक या तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों नौनिहालों के सपनों की सामूहिक हत्या है जिन्होंने अपनी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना सजाया था। सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के लिए शायद यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना और नई तारीख का ऐलान करने भर की औपचारिकता हो, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जिनके लिए यह परीक्षा महज एक कागज का टुकड़ा नहीं थी। महंगाई और आर्थिक विषमता के इस दौर में, यह परीक्षा गरीबी, अभाव और वर्षों के पारिवारिक संघर्षों से बाहर निकलने का एकमात्र दरवाजा थी, जिसे भ्रष्टाचार की दीमक ने ढहा दिया है।

प्रशासनिक गलियारों से जब एक रूखा सा बयान आता है कि अनियमितता के कारण परीक्षा रद्द की जाती है, तो एक वाक्य में पूरी जिम्मेदारी की इतिश्री कर दी जाती है। पर क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीति-निर्धारक उस मानसिक आघात का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कोटा या प्रयागराज की तंग गलियों में दस-बाय-दस के कमरों में बंद छात्र झेलता है? वह छात्र जो अपनी किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही अपनों से दूर हो जाता है, घर का स्वाद भूल जाता है और त्योहारों की खुशियों को केवल किताबों के पन्नों में तलाशता है। कोचिंग हब में पढ़ रहे हजारों बच्चों के पीछे केवल उनकी मेहनत नहीं, बल्कि एक पिता का वह कठिन परिश्रम होता है जिसने शायद अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखी होती है, या एक मां की वह तपस्या होती है जिसने अपनी दवा के पैसे बचाकर बेटे की भारी-भरकम फीस भरी होती है। जब पेपर लीक की खबर आती है, तो वह केवल एक पर्चा नहीं फटता, बल्कि उस पूरे परिवार की उम्मीदों की रीढ़ टूट जाती है। क्या कोई भी नई तारीख उस मानसिक अवसाद और टूटे हुए भरोसे की भरपाई कर सकती है, जो एक छात्र परीक्षा केंद्र से मुस्कुराते हुए निकलने के बाद घर लौटते समय महसूस करता है? सवाल यह भी उठता है कि उच्च सुरक्षा और तकनीकी चाक-चौबंद के बड़े-बड़े दावों के बीच राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का अभेद्य माना जाने वाला तंत्र कैसे भेद दिया जाता है? क्या हमारे देश का शिक्षा माफिया अब सरकारी सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसियों से भी अधिक शक्तिशाली और आधुनिक हो चुका है? पेपर की सेटिंग, प्रिंटिंग, परिवहन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की प्रक्रिया में एक ऐसी दीवार होनी चाहिए थी जिसे हिलाना नामुमकिन हो, लेकिन अगर उसमें बार-बार सेंध लग रही है, तो यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जड़ें तंत्र के भीतर बहुत गहरी धंसी हुई हैं। यह केवल एक सूचना का रिसाव नहीं है, बल्कि देश की बौद्धिक सुरक्षा और उसकी योग्यता के आधार पर की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक है। विडंबना देखिए कि हर कुछ वर्षों में एक बड़ा घोटाला सामने आता है, कुछ दिन टीवी पर सुर्खियां बनती हैं, आक्रोश फूटता है और फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जाती है—जांच कमेटियों का गठन, कुछ मोहरों की गिरफ्तारियां और अंत में मामला ठंडे बस्ते में। इसी लचर न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का लाभ उठाकर माफिया फिर से नए शिकार की तलाश में सक्रिय हो जाते हैं।

अब समय केवल सांत्वना देने या जांच कमेटियों के पीछे छिपने का नहीं है, बल्कि ऐसे कठोर प्रहार करने का है जो एक मिसाल बन सकें। जब तक दोषियों के मन में व्यवस्था का खौफ नहीं होगा, यह सिलसिला कभी नहीं थमेगा। इस अपराध को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना अनिवार्य है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के भविष्य के साथ गद्दारी है। इसमें शामिल हर व्यक्ति, चाहे वह आयोग का बड़ा अधिकारी हो, प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी हो या सॉल्वर गैंग का सदस्य, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बने। केवल सजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिस भी शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर की संलिप्तता रत्ती भर भी पाई जाए, उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। उनकी संपत्तियों को कुर्क कर उसे उन छात्रों के मुआवजे में लगाना चाहिए जिनका समय और पैसा इस व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। न्याय में देरी माफियाओं के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, इसलिए शिक्षा से जुड़े इन घोटालों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन समय की मांग है। एक प्रतिभाशाली बच्चा जब यह देखता है कि उसकी वर्षों की तपस्या और ईमानदारी पर सेटिंग करने वालों का पैसा और रसूख भारी पड़ रहा है, तो उसका लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। युवाओं का यह सामूहिक मोहभंग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी भी बाहरी आक्रमण से कहीं ज्यादा घातक है। यह स्थिति मेधावी छात्रों को पलायन या फिर अवसाद के रास्ते पर धकेलती है। दोषी कोई भी हो, उसकी अंतिम जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक धर्म है। अब शब्दों के मायाजाल और राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर धरातल पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। राष्ट्र का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसा माहौल दे रहे हैं। यदि आज हमने इस सड़ांध को जड़ से नहीं निकाला, तो कल की मेधा कभी हमें माफ नहीं करेगी। जब व्यवस्था स्वयं भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ ले, तो एक आम छात्र की कलम निहत्थी हो जाती है। यह समय सत्ता के लिए आत्ममंथन का है कि वह नोटों की गड्डियों और माफियाओं के गठजोड़ के सामने अपनी रीढ़ को झुकने देगी या फिर उस छात्र की आंखों के पानी को पोछेगी जिसने कड़ी धूप में परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होकर एक सुनहरे कल का सपना देखा था।

अंततः, अब बस न्याय का आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि व्यवस्था के भीतर वह परिवर्तन चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि किसी की मेहनत का सौदा चंद रुपयों में न हो सके। उन अनगिनत आंखों की चमक को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जो आज इस अंधेरे तंत्र में धुंधली पड़ रही हैं। अब समय आ गया है कि योग्यता के सम्मान को व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया जाए, ताकि कल जब कोई बच्चा अपनी मेहनत से खुद इबारत लिखे, तो उसे यकीन हो कि उसके भविष्य की चाबी किसी दलाल की जेब में नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रतिभा के हाथों में सुरक्षित है। व्यवस्था की चुप्पी अब अपराध मानी जाएगी, क्योंकि शांत रहना भी इस माफिया तंत्र को ऑक्सीजन देने जैसा ही है। देश का स्वाभिमान अब उन परीक्षा पत्रों की गरिमा में ही सुरक्षित है। सरकार को यह समझना होगा कि कलम की ताकत जब हताशा में बदलती है, तो वह किसी भी सिंहासन की नींव हिलाने का माद्दा रखती है। समाधान अब कल पर नहीं टाला जा सकता, क्योंकि लाखों युवाओं का धैर्य अपनी अंतिम सीमा पर है।

कला और साहित्य के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ की शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और लोक परंपरा केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समाज को दिशा देने का कार्य भी किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने सदैव मानव जीवन को नैतिकता, अध्यात्म, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया है। आज आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे समय में भारतीय कला और साहित्य के माध्यम से अपनी ज्ञान परंपरा का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस दिशा में भारतीय शिक्षण मंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो भारतीय शिक्षा और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य कर रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यह हमारी लोककथाओं, धार्मिक ग्रंथों, लोकगीतों, नाटकों, चित्रकलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में भी जीवित है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों में जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य और समाज निर्माण के सिद्धांत समाहित हैं। इन ग्रंथों ने भारतीय समाज को सदियों तक दिशा प्रदान की है। भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने का कार्य किया है।

मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में ग्रामीण जीवन, सामाजिक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित किया। उनकी कहानियाँ और उपन्यास भारतीय समाज की वास्तविकता को सामने लाते हैं। इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्र प्रेम और आत्मसम्मान की भावना को अपने साहित्य में स्थान दिया। इन साहित्यकारों की रचनाएँ केवल साहित्य नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। यदि नई पीढ़ी इन रचनाओं को पढेगी , तो वह अपनी संस्कृति और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकेगी।

भारतीय कला भी ज्ञान परंपरा के संरक्षण का सशक्त माध्यम रही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक, भरतनाट्यम, लोकनृत्य, मधुबनी चित्रकला और वारली कला जैसी परंपराएँ भारत की सांस्कृतिक पहचान हैं। इन कलाओं में भारतीय जीवन दर्शन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल सुर और ताल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को शांति प्रदान करने का माध्यम भी है। लोकनृत्य और लोकगीत समाज की परंपराओं, त्योहारों और सामाजिक जीवन को जीवंत बनाए रखते हैं।

आज के समय में युवा पीढ़ी आधुनिक तकनीक और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अधिक आकर्षित हो रही है। इसके कारण भारतीय भाषाओं, लोककलाओं और साहित्य के प्रति रुचि कम होती जा रही है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह संस्था विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं, साहित्य, कला और नैतिक मूल्यों के महत्व से परिचित कराती है। विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित की जाती है।

भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता, अनुशासन, सेवा और प्रकृति प्रेम की शिक्षा भी दी जाती थी। भारतीय शिक्षण मंडल इसी परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह संस्था मानती है कि यदि शिक्षा अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ी होगी, तभी विद्यार्थी एक अच्छे नागरिक और जिम्मेदार इंसान बन पाएँगे।

डिजिटल युग में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। आज इंटरनेट, ई-पुस्तकों और ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा भारतीय साहित्य और कला को विश्वभर तक पहुँचाया जा सकता है। अनेक विद्यालय और संस्थाएँ डिजिटल माध्यम से भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। इससे नई पीढ़ी आधुनिक तकनीक के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ रही है।

नई शिक्षा नीति 2020 ने भी भारतीय भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को विशेष महत्व दिया है। इससे भारतीय कला और साहित्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अपनी संस्कृति और परंपराओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। यह परिवर्तन भारतीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय कला और साहित्य हमारी संस्कृति की आत्मा हैं। इनके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों से सुरक्षित रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझें, उसका सम्मान करें और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। भारतीय शिक्षण मंडल जैसे संगठन इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यदि समाज, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को अपनाएं, तो हमारी ज्ञान परंपरा सदैव जीवित और समृद्ध बनी रहेगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

झालमुड़ी की झाल से झुलसी सियासत

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

मालवी बोली के स्वयंभू प्रकांड पंडित समझने वाले पंडित शिवनारायण जी बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद मॉर्निंग वॉक के दौरान मालवी में बोले टीएमसी झालमुड़ी की झाल से असी झुलसी... असी झुलसी की सियासत के भविष्य के तृण तृण से मोहताज हो गई। वे बोले झालमुड़ी के झाल की इतनी चरपराहट थी कि अच्छों-अच्छों की चपर-चपर के पैर काट दिए और सत्ता से हटाने वाली झालमुड़ी की झाल से पूरी सियासत झाल झाल करने लगी।

मालवी में झालमुड़ी को जब पंडित जी परिभाषित कर रहे थे इस बीच हिंदी इंग्लिश के बिचौलिए हिंगलिश का इस्तेमाल करने वाले सुनील भैया बोल पड़े अरे झालमुड़ी एक स्ट्रीट फूड है। उसको सड़क, फुटपाथ,मेलो ठेलो, सार्वजनिक स्थान,पार्क फेरी वाले, रेहड़ी,पटरी पर बेचे जाने वाला एक तैयार व्यंजन है जो चलते फिरते खाया जा सकता है इस सड़क के फूड झालमुड़ी ने अपने आप को सत्ता का सत्ताधीश मानने वालों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जिन्हें सत्ता की चाट लग गई थी उन सत्ता चटोरों को झालमुड़ी जैसी सड़क के फूड ने सड़क किनारे कर सड़क छाप बनने के लिए मजबूर कर दिया।

वे बोले स्ट्रीट पर रहने वाले और स्ट्रीट पर होने वाली गतिविधि अपनी छाप छोड़े बगैर नहीं रहती है। जिस तरह स्ट्रीट फूड था बोलबाला है इस तरह स्ट्रीट डॉग भी अपनी अहमियत, असलियत, अपना आक्रोश बता चुके हैं ।स्ट्रीट डॉग से न केवल सरकारे,आम अवाम वरन ,सुप्रीम, तक परेशान है। स्ट्रीट डागों को स्ट्रीट से हटाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट,अनेक निर्देश अनेक परिपत्र जारी होते हैं लेकिन डॉग ऐसे हैं कि वे अपनी स्ट्रीट छोड़ते ही नहीं है। उन्हें सड़क छाप बनकर जीना ही अच्छा लगता और कोई उन्हें छेड़खानी करता है तो डाग से पीछा छुड़ाने वालों को वे सड़क छाप बना देते हैं। अपनी प्रवृत्ति से रेबीज का टोटा ला देते है । इस पर कॉलोनी के स्ट्रीट डांसर लचकराम जी बोले अरे स्ट्रीट की बात चली है तो स्ट्रीट डांस जिसे मालवी में सड़क छाप नृत्य भी कहते हैं जो खुले स्थान, सड़कों ,गली मोहल्लो, जलसो ,समारोहों में स्ट्रीट यानी सड़क पर बेंड बाजे बारात के साथ होता है वह अच्छी-अच्छी थ्री और फाइव स्टार में होने वाले तरह-तरह के पाश्चात्य डांस को पछाड़ देता है। वे बोले अरे स्ट्रीट वेयर पहने युवक जब सड़क पर निकलते हैं तो वह अलग संस्कृति वाली पहचान बताते हैं।

इस पर इंदौर से लोटे चंद्रबाबू बोले इंदौर को स्टेट फूड की राजधानी माना जाता है यहां के स्ट्रीट फूड के स्वाद बेमिसाल है। 56 दुकान का स्ट्रीट फूड इंदौर का और खाने वाले दोनों का 56 इंच का सीना बढ़ा देता है ।इंदौर स्ट्रीट फूड चटोरों के लिए स्वर्ग है। यहां सड़क पर खाने पीने वाले शौकीनों का अड्डा बन जाता है । दिन में सोना चांदी और रात में सराफा में स्ट्रीट फूड को खाने वालों का मेला लग जाता है। अनेक शहरों का स्ट्रीट फूड अद्भुत परंपरा का होकर स्ट्रीट फूड की अहमियत को बताता है ।इस पर राजनीति में टिकट के लिए दिल्ली की गलियों में भटकने वालों नेताजी बोले दिल्ली की पराठे गली के पराठे भी स्ट्री फूड है और चांदनी चौक पहाड़गंज के छोले भटूरे को स्ट्रीट फूड में सर्वाधिक लोकप्रिय बताने लगे ।वे बोले बड़े शहरों में, स्ट्रीट साइन,गली मोहल्लों की पहचान बताते है गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की रोशनी सुरक्षा और विजिबिलिटी प्रदान करती है वह बड़ी सड़कों की लाइटों के हाई मास्क को भी चुनौती देती है। इस पर कोलकाता में मिलने वाली झाल मुड़ीको चटपटा स्पीड फूड बताते हुए डॉ विश्वास बोले बंगाली संस्कृति का हिस्सा बनी स्ट्रीट में मिलने वाली झालमुड़ी अपडेट का जब देश के मुखिया ने स्वाद का हिस्सा बनी तो बंगाल में झालमुडी के स्वाद की तरह उसने सत्ता का स्वाद ही बदल दिया। इस चटपटे झरपट स्वाद वाले स्ट्रीट फूड झाल मुड़ी ने ऐसी झाल जलाई की खोखले ममत्व की सारी पोल खुल गई और स्ट्रीट वाली झाल मुड़ी ने सत्ता का स्वाद पलटने का श्रेय ले लिया और अब वह स्ट्रीट से बड़ी होटल शादी समारोह का मेनू बन गई है। ऐसी झाल मुड़ी जैसे व्यंजनों की झाल लोकतंत्र में अच्छे बुरे का सिलेक्शन कर झुलसाती रहे! झालमुड़ी के लोकतंत्री स्वाद की जय हो...!

न्याय सुविधा

डॉ. सुधीर कुमार

(कुरुक्षेत्र विवि में सहायक प्रोफेसर)

अशोक के 'धम्म' से डिजिटल 'लोक अदालत' तक

भारतीय न्यायशास्त्र के विशाल आकाश में 'लोक अदालत' उस ध्रुव तारे की भाँति है, जो सदियों पुरानी जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के अंधकार में आम आदमी को त्वरित और सुलभ न्याय का मार्ग दिखाता है। 'न्याय में देरी, न्याय की अवहेलना है' इस विडंबना को समाप्त करने के लिए लोक अदालत एक ऐसी संजीवनी बनकर उभरी है, जिसने 'मुकदमेबाजी' को 'समाधान' में बदल दिया है। यह केवल एक कानूनी मंच नहीं है, बल्कि न्याय का वह 'मानवीय चेहरा' है जहाँ न्यायाधीश और पक्षकार आमने-सामने बैठकर विवादों की कड़वाहट को आपसी सहमति की मिठास से समाप्त करते हैं।

आधुनिक भारत में, जहाँ न्यायालयों में लंबित मामलों का आंकड़ा करोड़ों को छू रहा है, वहाँ लोक अदालत गांधीवादी दर्शन और प्राचीन भारतीय आदर्शों का एक सफल समन्वय प्रस्तुत करती हैं। इतिहास साक्षी है कि भारत में न्याय कभी केवल 'दंड' का विधान नहीं रहा, बल्कि 'सद्भाव' की स्थापना का माध्यम रहा है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में 'राजुकों' (न्यायिक अधिकारियों) को निर्देश दिया था कि उनका कार्य विवादों को मात्र कानूनी रूप से सुलझाना नहीं, बल्कि समाज में 'धम्म' और नैतिकता को अक्षुण्ण रखना है। न्याय की यही भावना मध्यकाल में महारानी अहिल्याबाई होल्कर के शासन में भी जीवंत रही, जहाँ न्याय 'लोक-दरबार' का हिस्सा था और वे स्वयं मध्यस्थता के जरिए पक्षों की शत्रुता समाप्त करती थीं। आज की लोक अदालतें वास्तव में अशोक के 'धम्म-न्याय' और अहिल्याबाई के 'लोक-कल्याणकारी न्याय' का ही आधुनिक विस्तार हैं, जो प्राचीन पंच-परमेश्वर की परंपरा को वर्तमान न्यायिक ढांचे से जोड़ती हैं।

समय बदला और ब्रिटिश राज के दौरान भारत में औपचारिक 'एडवरसैरियल' कानूनी प्रणाली आई, जिसने न्याय को खर्चीला और समय लेने वाला बना दिया। आजादी के बाद, इस खाई को पाटने के लिए 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में पहली आधुनिक 'लोक अदालत' का आयोजन किया गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने वैकल्पिक विवाद समाधान की नींव रखी। आगे चलकर, संविधान के अनुच्छेद 39 के 'समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता' के संकल्प को साकार करने के लिए 'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' पारित किया गया, जिसने लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। लोक अदालत की कार्यप्रणाली और क्षेत्राधिकार को समझना न्यायिक सुगमता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका संचालन मुख्य रूप से 'कानूनी सेवा प्राधिकरणों' द्वारा किया जाता है, जो विवादों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर उनका समाधान करते हैं। पहली श्रेणी में लंबित मामले आते हैं, जो पहले से ही किसी न्यायालय में विचाराधीन हैं और जहाँ पक्षों के बीच आपसी सुलह की थोड़ी भी गुंजाइश बची होती है। दूसरी ओर, मुकदमों से पहले के मामले वे विवाद हैं जो अभी तक औपचारिक रूप से अदालत की चौखट तक नहीं पहुंचे हैं; इन्हें लोक अदालत के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझा लिया जाता है ताकि भविष्य की लंबी, खर्चीली और मानसिक रूप से थका देने वाली कानूनी लड़ाई से बचा जा सके। जहाँ तक इसके क्षेत्राधिकार और मामलों की प्रकृति का प्रश्न है, लोक अदालत का दायरा अत्यंत विस्तृत और समावेशी है। इसके अंतर्गत संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार और भूमि अधिग्रहण जैसे दीवानी मामले प्रमुखता से आते हैं। साथ ही, यह श्रम विवादों (जैसे वेतन और ग्रेच्युटी) और आर्थिकमामलों (जैसे बैंक रिकवरी एवं धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस) के त्वरित निस्तारण का एक सशक्त मंच है। जनोपयोगी सेवाओंजैसे बिजली, पानी, टेलीफोन और बीमा से जुड़े विवादों का समाधान भी यहाँ प्रभावी ढंग से किया जाता है। विशेष रूप से, लोक अदालत उन शमनीय आपराधिकमामलों में रीढ़ की हड्डी साबित होती है जहाँ कानून दोनों पक्षों को समझौते की अनुमति देता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि गंभीर प्रकृति के अपराध और तलाक जैसे संवेदनशील मामले, जहाँ सुलह की कोई संभावना न हो, इसके वैधानिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि लोक अदालत न्याय वितरण का एक सशक्त और संतुलित माध्यम हैं, जहाँ पीटी थॉमस बनाम थॉमस जोब (2005) के अनुसार इसके 'अवॉर्ड' को सिविल कोर्ट की डिक्री मानकर अंतिम और अपरिवर्तनीय शक्ति दी गई है ताकि मुकदमेबाजी का अंत हो सके, वहीं स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जलौर सिंह (2008) के माध्यम से यह सीमा भी तय की गई है कि बिना आपसी सहमति के लोक अदालत स्वयं निर्णय नहीं थोप सकती और ऐसे मामले नियमित कोर्ट को लौटाने अनिवार्य हैं। समकालीन समय (2024-2026) में, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में ई-लोक अदालतों और 'विशेष लोक अदालत सप्ताह' जैसे नवाचारों ने न्याय को जनता के करीब पहुँचाया है, जहाँ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुधारात्मक रूप से उन मुकदमों की पहचान के लिए किया जा रहा है जिनमें सुलह की गुंजाइश अधिक है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और स्थायित्व दोनों सुनिश्चित हुए हैं। यद्यपि वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणा वैश्विक है, किंतु भारत की लोक अदालत प्रणाली कई मायनों में 'यूनिक' है। अमेरिका में 'मल्टी-डोर कोर्टहाउस' का प्रचलन है, चीन में 'पीपुल्स मेडिएशन कमिटी' सक्रिय हैं औरब्रिटेन में 'अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन' पर जोर दिया जाता है। लेकिन भारत की लोक अदालत इन सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि ये 'वैधानिक शक्ति' और 'स्वैच्छिक भावना' का एक अद्भुत मिश्रण हैं। यहाँ किसी वकील की अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती, कोई अदालती शुल्क नहीं लगता (और यदि लगा हो तो वह वापस कर दिया जाता है), और निर्णय पर अपील का कोई प्रावधान न होना इसे 'त्वरित न्याय' का विश्वव्यापी रोल मॉडल बनाता है।

आज हम 'न्याय के डिजिटलीकरण' के युग में हैं। ई-लोक अदालत अब एकवास्तविकता हैं, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक किसान अपने गाँव से और एक कॉर्पोरेट अधिकारी अपने दफ्तर से बैठकर विवाद सुलझा रहे हैं। बिहार जैसे राज्यों में ट्रैफिक चालान के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट' की ऑनलाइन प्रक्रिया इसका सफल उदाहरण है। भविष्य में, ब्लॉकचेन तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से स्थायी लोक अदालतों को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। लोक अदालतों की अभूतपूर्व सफलता के बाद भी कुछ ऐसी मौलिक चुनौतियां मौजूद हैं, जो इसके पूर्ण प्रभाव को सीमित करती हैं। विशेषकर ग्रामीण अंचलों में कानूनी साक्षरता का अभाव एक बड़ी बाधा है, जहाँ लोग अपने अधिकारों और लोक अदालत की स्वैच्छिक प्रकृति से अनभिज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी यह भी देखा गया है कि सदस्यों द्वारा विवाद सुलझाने की जल्दबाजी में पक्षकारों पर समझौते के लिए अनचाहा दबाव बनाया जाता है, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

लोक अदालतों को मात्र 'मामला निपटाने वाली मशीन' के बजाय वास्तविक 'न्याय का केंद्र' बनाना अनिवार्य है। इसके लिए मध्यस्थों को कानूनी ज्ञान के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे संवेदनशीलता से विवाद सुलझा सकें। साथ ही, 'स्थायी लोक अदालतों' का विस्तार हर जिले और उपमंडल स्तर तक करना ज़रूरी है ताकि आम आदमी को घर के पास ही सम्मानजनक न्याय मिल सके। वस्तुतः लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली की 'रीढ़' है, जो प्राचीन न्याय-बोध को आधुनिक रूप देती है। यहाँ केवल फाइलें बंद नहीं होती, बल्कि सत्य की जीत के साथ पक्षों के बीच की कड़वाहट भी समाप्त होती है, जिससे सामाजिक रिश्तों की मर्यादा बनी रहती है। एक विकसित भारत के निर्माण में, जहाँ सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति साथ-साथ चलते हैं, लोक अदालत 'सामाजिक सद्भाव' की गारंटी हैं। यह गांधीजी के उस स्वराज्य के सपने को साकार करती है जहाँ न्याय महंगा नहीं, बल्कि हर नागरिक का सहज अधिकार है। लोक अदालत हमें सिखाती है कि महानतम न्याय वह है जो कानून की किताबों से नहीं, बल्कि मनुष्यों के हृदय और आपसी विवेक से उत्पन्न होता है। यह 'न्याय सबके लिए' की दिशा में वास्तव में एक क्रांतिकारी और शाश्वत कदम है।

श्रीमंत छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर विशेष

अमित राव पवार

युवा लेखक

वह ज्वाला जिसे यातनाएँ भी बुझा न सकीं

संभाजी महाराज की छवि प्राय: केवल रणभूमि के योद्धा के रूप में प्रस्तुत की जाती है,जबकि वे असाधारण विद्वान भी थे। संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और पुर्तगाली जैसी भाषाओं पर उनका अधिकार था। उन्होंने कम आयु में ही 'बुधभूषणम्' जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की। यह तथ्य बताता है कि उनकी तलवार जितनी तेज थी,उनकी बुद्धि उससे कहीं अधिक प्रखर थी। वे जानते थे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल सेना में नहीं,बल्कि उसकी संस्कृति और ज्ञान परंपरा में निहित होती है। 1680 में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य व हिंदवी स्वराज तथा भारतभूमि पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा।

भारतीय इतिहास का गगन अनेक वीरों की गाथाओं से आलोकित है,किंतु कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते,बल्कि राष्ट्र की आत्मा में सदैव जीवित रहते हैं। श्रीमंत छत्रपति संभाजी महाराज ऐसेही एक अमर व्यक्तित्व हैं,जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान, विद्वता और बलिदान का अद्वितीय संगम था। दुर्भाग्य से इतिहास के अनेक पन्नों में उनके व्यक्तित्व को उतनी व्यापकता नहीं मिली, जिसके वे वास्तविक (deserve) अधिकारी थे। उनके जीवन को केवल युद्धों और बलिदान तक सीमित कर दिया गया,जबकि सत्य यह है कि संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं,बल्कि राष्ट्रचेतना के प्रखर प्रहरी थे। आज जब समाज वैचारिक भ्रम, सांस्कृतिक विस्मृति और इतिहास की अधूरी व्याख्याओं से जूझ रहा है,तब संभाजी महाराज का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि राष्ट्र केवल तलवारों से नहीं,बल्कि आत्मसम्मान,संस्कृति और दृढ़ संकल्प से सुरक्षित रहता है।

14 मई 1657 को पुरंदर किले में जन्मे श्रीमंत संभाजी महाराज ने बाल्यकाल से ही संघर्ष को अपनी नियति के रूप में देखा। वे श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे,किंतु राजमहलों का वैभव उनके जीवन की पहचान नहीं बना। बाल्यकाल में ही माता सईबाई का साया सिर से उठ गया। इसके बाद उनका पालन-पोषण राजमाता जीजाबाई के संरक्षण में हुआ,जिन्होंने उनके भीतर धर्म,स्वराज्य और राष्ट्र गौरव के ऐसे संस्कार रोपे,जो अंतिम सांस तक उनके व्यक्तित्व की आधारशिला बने रहे। मात्र नौ वर्ष की आयु में पुरंदर की संधि के तहत उन्हें मुगल दरबार में राजनीतिक बंधक बनाकर भेज दिया गया। सोचिए,जिस आयु में सामान्य बालक खेल और सपनों की दुनिया में जीता है, उस आयु में संभाजी महाराज को शत्रुओं के बीच रहकर राजनीति,छल और सत्ता का कठोर यथार्थ देखना पड़ा। किंतु यही परिस्थितियाँ आगे चलकर उन्हें अदम्य साहस का प्रतीक बनाने वाली थीं। उन्होंने भय को कभी अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। विपरीत परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं,बल्कि लोहे से भी अधिक मजबूत बना दिया।

संभाजी महाराज की छवि प्रायः केवल रणभूमि के योद्धा के रूप में प्रस्तुत की जाती है,जबकि वे असाधारण विद्वान भी थे। संस्कृत,मराठी,हिंदी,फारसी और पुर्तगाली जैसी भाषाओं पर उनका अधिकार था। उन्होंने कम आयु में ही 'बुधभूषणम्' जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की। यह तथ्य बताता है कि उनकी तलवार जितनी तेज थी,उनकी बुद्धि उससे कहीं अधिक प्रखर थी। वे जानते थे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल सेना में नहीं,बल्कि उसकी संस्कृति और ज्ञान परंपरा में निहित होती है। 1680 में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य व हिंदवी स्वराज तथा भारतभूमि पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। भीतर सत्ता संघर्ष और बाहर मुगलों का भीषण आक्रमण। उस समय मुगल सत्ता का सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब दक्षिण में स्वराज्य की जड़ों को समाप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ उतर चुका था। उसे विश्वास था कि

महाराज शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य ओर स्वराज का स्वप्न इस देश से शीघ्र ही बिखर जाएगा। किंतु यही वह क्षण था,जब संभाजी महाराज ने अपने अद्वितीय नेतृत्व से इतिहास की दिशा बदल दी।

16 जनवरी 1681 को उन्होंने मराठा साम्राज्य (हिंदवी स्वराज) की बागडोर संभाली और मुगलों के विरुद्ध ऐसा प्रतिरोध खड़ा किया,जिसने औरंगजेब की वर्षों पुरानी महत्वाकांक्षाओं को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने नौ वर्षों के शासनकाल में 140 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। यह केवल वीरता नहीं थी,बल्कि असाधारण रणनीति,नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निष्ठा का परिचायक था उन्होंने मुगलों को हर मोर्चे पर चुनौती दी। संभाजी महाराज का सबसे प्रेरक पक्ष था–उनका अटूट स्वाभिमान। वे जानते थे कि यदि स्वराज्य झुक गया,तो केवल एक राज्य नहीं,बल्कि भारतीय अस्मिता पर आघात होगा। इसलिए उन्होंने संघर्ष को जीवन का धर्म बना लिया वे सत्ता के लिए नहीं,बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। फरवरी 1689 में संगमेश्वर में विश्वासघात के कारण वे मुगलों के हाथों बंदी बना लिए गए। इसके बाद इतिहास ने क्रूरता की वह पराकाष्ठा देखी,जो विश्व मे ओर कहि नही दिखाई दी।जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब ने उन्हें धर्म परिवर्तन कर जीवनदान पाने का प्रस्ताव दिया। यह केवल एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन का प्रश्न नहीं था,बल्कि स्वराज्य की आत्मा को झुकाने का प्रयास था। किंतु संभाजी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु स्वीकार है,परंतु आत्मसमर्पण नहीं। उन पर (लगभग 40 दिनों से भी अधिक) अमानवीय यातनाएँ दी गईं। शरीर को क्षत-विक्षत किया गया,अपमानित किया गया,लेकिन उनकी आत्मा को झुकाया नहीं जा सका। वे अंत तक दृढ़ रहे। 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई,किंतु वास्तव में उस दिन एक योद्धा नहीं मरा–एक विचार अमर हो गया। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज को समाप्त नहीं किया,बल्कि उसे और अधिक प्रचंड बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद स्वराज्य की ज्वाला और अधिक भड़क उठी। अंततः वही संघर्ष मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। जिस 'औरंगजेब' ने हिंदवी स्वराज तथा मराठाओं को मिटाने का सपना देखा था,वह स्वयं दक्कन की धरती पर संघर्ष करते-करते टूट कर मृत्यु को जा मिला परंतु हिंदवीस्वराज,मराठाओं ओर सम्पूर्ण भारतभूमि पर एकाधिकार नही कर पाया।

आज आवश्यकता इस बात की है कि श्रीमंत संभाजी महाराज को केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित न रखा जाए,बल्कि उन्हें भारतीय स्वाभिमान के जीवंत प्रतीक के रूप में समझा जाए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों,यदि मनुष्य के भीतर राष्ट्र प्रेम,आत्मबल और सत्य के प्रति निष्ठा हो,तो वह किसी भी साम्राज्य की नींव हिला सकता है। श्रीमंत छत्रपति संभाजी महाराज केवल मराठा इतिहास के नायक नहीं हैं, वे उस भारतीय आत्मा के प्रतीक हैं,जो अन्याय के सामने कभी झुकते नहीं। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव यह प्रेरणा देता रहेगा कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है।

दृष्टिकोण

संध्या अग्रवाल

लेखक साहित्यकार हैं।

फेक न्यूज़ का बढ़ता खतरा और समाज पर असर

आज के समय में यह भी देखा जा रहा है कि फेक न्यूज़ केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही है। कई बार गलत सूचनाओं के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। इस प्रकार फेक न्यूज़ का प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। समाज पर फेक न्यूज़ का प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक है। इससे लोगों का विश्वास मीडिया, प्रशासन और अन्य संस्थाओं से कमजोर होने लगता है।

आज के डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह अत्यंत तेज़ हो गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने हर व्यक्ति को खबरों तक त्वरित पहुंच प्रदान की है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक गंभीर समस्या भी तेजी से उभर कर सामने आई है–फेक न्यूज़। झूठी, भ्रामक या आधी-अधूरी जानकारी का प्रसार आज समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

फेक न्यूज़ का सबसे खतरनाक पहलू इसकी तीव्र गति है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कोई भी खबर कुछ ही मिनटों में हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब लोग बिना सत्यापन किए ऐसी खबरों को आगे साझा कर देते हैं। इससे अफवाहें फैलती हैं, जो समाज में भ्रम, डर और तनाव की स्थिति उत्पन्न करती हैं। कई बार यह स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने लगता है और विवाद तक खड़े हो जाते हैं।

आज के समय में यह भी देखा जा रहा है कि फेक न्यूज़ केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही है। कई बार गलत सूचनाओं के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। इस प्रकार फेक न्यूज़ का प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है।

समाज पर फेक न्यूज़ का प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक है। इससे लोगों का विश्वास मीडिया, प्रशासन और अन्य संस्थाओं से कमजोर होने लगता है। जब सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, तब आम नागरिक असमंजस में पड़ जाता है। इसके अलावा, यह लोकतंत्र के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि यदि नागरिक गलत जानकारी के आधार पर अपने विचार और निर्णय बनाते हैं, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है।फेक न्यूज़ के प्रसार के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।

सबसे प्रमुख कारण है डिजिटल साक्षरता की कमी। आज भी बड़ी संख्या में लोग यह नहीं समझ पाते कि किसी खबर की सत्यता कैसे जांची जाए।

इसके अतिरिक्त, कुछ लोग जानबूझकर भी गलत सूचनाएं फैलाते हैं ताकि समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा की जा सके। सनसनीखेज और आकर्षक खबरों की ओर लोगों का झुकाव भी इस समस्या को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में तेजी से ध्यान आकर्षित करने की होड़ भी फेक न्यूज़ को बढ़ावा देती है। कई बार लोग अधिक लाइक, शेयर और लोकप्रियता पाने के लिए बिना पुष्टि की जानकारी साझा कर देते हैं। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे एक आदत का रूप ले लेती है, जिससे गलत सूचनाओं का प्रसार और अधिक बढ़ जाता है।

इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसी भी समाचार को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और संदिग्ध खबरों से दूरी बनानी चाहिए। सरकार और मीडिया संस्थानों को भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे कि फेक न्यूज़ पर निगरानी, जागरूकता अभियान और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर छात्रों को डिजिटल साक्षरता और तथ्य जांच (फैक्ट-चेकिंग) के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे सही और गलत के बीच अंतर समझ सकें। यह समय की मांग है कि हम तकनीक का उपयोग समझदारी से करें और उसके दुष्प्रभावों से खुद को सुरक्षित रखें।अंततः, फेक न्यूज़ से बचाव केवल कानून या नियमों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जागरूक और जिम्मेदार समाज की आवश्यकता है। यदि हम सभी सचेत होकर सही जानकारी को महत्व दें और झूठी खबरों को फैलाने से बचें, तो एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण किया जा सकता है।

अपने दामन पर बदहाली का दाग ओढ़े 100 बरस के जिला भोज चिकित्सालय को है कायाकल्प का इंतजार

बदहाली देख बिफरे नवागत कलेक्टर, व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश

राजेश शर्मा, धार। 100 बरस से अधिक का सफर तय कर चुका जिला भोज चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धार शहर ही नहीं अपितु जिलेवासियों के लिए 'लाइफलाइन' हैं। जिले के इस सबसे बड़े चिकित्सालय के कंधों पर जिले के नागरिकों की बेहतर सेहत का जिम्मा है लेकिन आलम यह कि तंत्र की नाकामी के चलते खुद अपनी सेहत के लिए संघर्ष कर रहा हैं। अपने दामन पर बदहाली का दाग ओढ़े जिला भोज चिकित्सालय को है कायाकल्प का इंतजार। खुद निरीक्षण के दौरान जिले के मुखिया (डीएम) जिला भोज चिकित्सालय अर्थात? 'लाइफलाइन' की बदरंग तस्वीरें देख दंग रह गए। नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना के कड़े रुख के बाद अब देखना यह होगा कि जिला भोज चिकित्सालय की कार्यप्रणाली में वास्तव में कोई बदलाव आता है या हालात फिर पुराने ढर्रे पर ही ।

नवागत कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी – जिला भोज चिकित्सालय की साख और व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना के अचानक निरीक्षण पर पहुँचने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी।कलेक्टर ने अस्पताल के वार्डों और परिसर का बारीकी से जायजा लिया, जहाँ उन्हें चारों ओर अव्यवस्था का अंबार मिला।

सफाई व्यवस्था ध्वस्त, संसाधनों का अभाव – अस्पताल के कई वार्डों में भारी गंदगी मिली, जिससे सफाई प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। कई वार्डों में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड तक उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

खास- खास

- कलेक्टर की एंट्री होते ही लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारी अपनी कमियां छिपाने के लिए व्यवस्थाएं सुधारने में जुट गए।
- कलेक्टर की दो टूकः सुधारें प्रक्रिया, मरीजों को न हो असुविधा।
- कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं का आधार होता है। यह एक ब्रीफ विजिट थी ताकि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बेसलाइन समझी जा सके। साफ-सफाई और कार्यप्रणाली की प्रक्रियाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

चुनौतियां ...

रेडियोलॉजिस्ट की कमी– अस्पताल में लंबे समय से स्थाई रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने का मुद्दा सामने आया है। कलेक्टर ने इस संबंध में शासन स्तर पर बात करने का आश्वासन दिया है।

जिला अस्पताल पर बोझ ज्यादा – कलेक्टर ने कहा कि सामान्य प्रसव और बुनियादी इलाज स्थानीय स्तर पर सिविल और प्राथमिक अस्पतालों में ही सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि जिला अस्पताल पर बोझ कम हो और मरीजों को भटकना न पड़े।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के सुधार केवल अधिकारियों के दौरे तक सीमित रहते हैं। लोगों ने मांग की है कि केवल औपचारिकता न की जाए, बल्कि स्थाई रूप से व्यवस्थाएं बदली जाएं।

नवागत कलेक्टर के कड़े रुख के बाद अब देखना यह होगा कि जिला भोज चिकित्सालय की कार्यप्रणाली में वास्तव में कोई बदलाव आता है या हालात फिर पुराने ढर्रे पर ही लौट आएंगी।

वर्ष 1872 से प्रारंभ मकान गणना कार्य पहली बार एचएलओ ऐप पर ऑनलाइन, शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण

सोहागपुर। वर्ष 1872 से प्रारंभ मकान जनगणना कार्य पूर्व के वर्षों में ऑफलाइन होता रहा है। किन्तु प्रदेश शासन के निर्देश पर अब मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य एचएलओ ऐप पर पहली बार ऑनलाइन किया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे सभी नागरिकों को सुविधा उपलब्ध होगी। नगरपालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि उक्त कार्य में प्रगणकों के द्वारा परिवार जनों से 34 प्रश्नों की जानकारी लेकर ऐप में दर्ज की गई है। जिसमें ऑनलाइन जनरेट होने वाले भवन नंबर को भवन पर अंकित किया गया है।

शत प्रतिशत मकान सूचीकरण – इसी क्रम में नगरपालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत किए जाने वाले मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य सोहागपुर शहरी चार्ज में दिनांक 01 मई से प्रारंभ होकर चार्ज अधिकारी नगरपालिका अधिकारी एवं फील्ड ट्रेनर राकेश रघुवंशी के निर्देशन में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत सोहागपुर के समस्त 15 वार्डों में 37 ब्लॉक बनाए गए थे ।जिनमें 35 प्रगणकों समेत 6 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था सभी ने मेहनत एवं लगन से 15 मई को पूर्ण किए जाने वाले कार्य को 3 दिवस पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया। जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के उपरांत अब सभी प्रगणकों को एचएलबी का नगरी नक्शा बना कर चार्ज अधिकारी को सौंपा जाना होगा ।जिसमें प्रत्येक वार्ड के घर,मंदिर,मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल,पार्क आदि को चित्रित किया जाएगा। नगर पंचायत परिषद सोहागपुर ने नर्मदापुरम जिले के 18 चार्ज में द्वितीय स्थान प्राप्त करके उल्लेखनीय प्रशंसा प्राप्त की है। सराहनीय कार्य में सफलता प्राप्त करने पर चार्ज जनगणना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को बधाई प्रेषित की है।

रेवा बनखेड़ी मार्ग पर अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से हटाया

सोहागपुर । कलेक्टर महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व सोहागपुर के निर्देश अनुसार सुभाष वार्ड क्रमांक 1 रेवा बनखेड़ी रोड के दोनों ओर से अतिक्रमण मुहिम के तहत अतिक्रमण बुलडोजर के माध्यम से हटाया गया ।उक्त कार्यवाही शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर नगर पंचायत परिषद एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल की टीम ने हटाया है ।मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने की मुहीम निरंतर जारी रहेगी ।इसके लिए दलों का गठन किया गया है ।इधर सोहागपुर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे पुष्पराज सिंह पटेल ने मुहिम का विरोध करते हुए कहा कि छोटे छोटे लोगों के अतिक्रमण हटाए जा रहें हैं ।

गेहूं खरीदी में शिथिलता के कारण प्रदेश का किसान परेशान: राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ अध्यक्ष कक्काजी

सोहागपुर । गेहूं खरीदी में शिथिलता के कारण प्रदेश का किसान परेशान हैं । हर जगह वेयरहाउसों के आसपास सैकड़ों ट्रेक्टर ट्रालियों में भरा हुआ आज़ पड़ा हुआ ।कई किसान तो किराये के ट्रेक्टर ट्रालियों में फसल लेकर पहुंचे हुए ।जिससे उन किसानों को ट्रेक्टर ट्राली का किराए का भुगतान भी करना पड़ रहा है ।किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है ।वहीं जिले भर में बरदान की कमी देखी जा रही । खुले में गेहूं पड़ा हुआ है ।बरसात भी करवट ले रही है ।इससे किसान अपनी फसल के नुकसान होने की संभावना से चिन्तित हो रहे हैं ।उक्त बात सोहागपुर के समीपवर्ती ग्राम किवलारी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रान्तीय उपाध्यक्ष केशरीसिंह पटेल के निवास पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी जी ने कहे ।उनको प्रान्तीय उपाध्यक्ष केशरीसिंह पटेल ने क्षेत्र के किसानों की परेशानी से अवगत कराया था ।कक्काजी ने कल कलेक्टर, कमिश्नर एवं संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की । प्रान्तीय उपाध्यक्ष केशरीसिंह पटेल ने बताया कि कक्काजी जी ने कहा है कि यदि शीघ्र ही किसानों की समस्याओं का निदान नहीं किया गया ।तो आन्दोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा ।इस आन्मेंदोलन के संबंध में रूपरेखा तैयार की जा रही है ।उल्लेखनीय है सोहागपुर ब्लाक ही नहीं माखननगर के ब्लाक में भी सैकड़ों ट्रेक्टर ट्राली लेकर अपने अपने निर्धारित खरीदी केन्द्रों के वेयरहाउसों के आसपास पर खड़े हैं ।इससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही ।एक तो बरसात होने की संभावना से नुकसान की आंशका तो दूसरी तरफ ट्रेक्टर ट्रालियों के किराए का भुगतान ।इसके पूर्व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी का स्वागत किया गया ।वहीं उन्होंने ग्राम किवलारी में रात्रि विश्राम किया ।

टीम वर्क प्रतिबद्धता से जनगणना 2027 : सोहागपुर ग्रामीण के समस्त 230 गणना ब्लॉकों का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण

सोहागपुर । टीम वर्क अनुशासन एवं प्रतिबद्धता के कारण जनगणना 2027 सोहागपुर ग्रामीण के समस्त 230 गणना ब्लाकों का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करके उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया है ।उल्लेखनीय है कि भारत की प्रथम चरण अंतर्गत हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग गणना कार्य में सोहागपुर ग्रामीण चार्ज ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करते अपने सभी 230 गणना ब्लाकों का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है । जिसमें सोहागपुर ग्रामीण चार्ज ने 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करके मिसाल कायम की है ।उक्त सफलता समस्त सुपरवाइजरों, प्रगणकों एवं संबंधित अधिकारियों के सतत परिश्रम, समन्वय और कर्तव्यनिष्ठा का परिणाम है ।इस उल्लेखनीय प्रर्दशन पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी तथा तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी, सोहागपुर राम किशोर झरबड़े ने इस उपलब्धि पर सभी सुपरवाइजरों एवं प्रगणकों एवं जनगणना कार्य में लगे स्टाफ को बधाई देकर कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है ।सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर उक्त उपलब्धि हासिल की है ।इस अवसर पर चार्ज अधिकारी राम किशोर झरवडे ने जनगणना कार्य में लगे सुपरवाईजर एवं कार्यालय स्टाफ के विपिन गिल्ला ,विजेन्द्र वर्मा, राहुल साहू ,संदीप कुशवाहा, अमितकुमार मिश्रा ,उमेश रघुवंशी, राहुल पटेल, हिमांशू चौरसिया आदि मिष्ठान खिला कर बधाई दी ।आपने अंत में कहा कि सोहागपुर ग्रामीण चार्ज की यह उपलब्धि अन्य के लिए प्रेरणादायक है । जो टीमवर्क, प्रतिबद्धता,अनुशासन एवं जिम्मेदारी की उत्कृष्ट मिसाल है ।

भाजपा ने अंतिम लड़ाई जीती, नीतू परमार की घर वापसी से मुलताई की राजनीति में नया मोड़

साढ़े तीन साल तक चली कानूनी और राजनीतिक जंग के बाद भाजपा मंच पर साथ दिखीं नीतू परमार और वर्षा गढ़ेकर, संयुक्त बयान ने बढ़ाई चर्चाएं

बैतूल। मुलताई की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित घटनाक्रम और चौंकाने वाले परिणामों के लिए जानी जाती रही है। एक बार फिर ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जिसने क्षेत्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद परमार ने एक बार फिर भाजपा में घर वापसी कर ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि भाजपा में शामिल होते समय पूर्व नपाध्यक्ष वर्षा गढ़कर भी उनके साथ मंच पर मौजूद थीं। यही नहीं, दोनों महिला नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया। राजनीतिक गलियारों में यह दृश्य इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब साढ़े तीन वर्षों तक न्यायालयों में लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। दरअसल, 15 पार्षद वाली नगर पालिका परिषद में भाजपा का बहुमत था, अध्यक्ष पद के लिए पार्टी ने वर्षा गढ़ेकर को अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। उस समय अध्यक्ष पद महिला सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। भाजपा की पार्षद रहीं नीतू परमार ने पार्टी के निर्णय से असहमति जताते हुए वर्षा गढ़ेकर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। राजनीतिक समीकरण उस समय पूरी तरह बदल गए थे। भाजपा बहुमत वाली परिषद में कांग्रेस के समर्थन से नीतू परमार को 9 मत प्राप्त हुए और वे नगरपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हो गईं। इसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। दूसरी ओर, अध्यक्ष पद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए वर्षा गढ़ेकर ने मुलताई न्यायालय में याचिका दायर की। यह मामला बाद में जबलपुर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस दौरान राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम लगातार बदलते रहे। दो बार नीतू परमार ने नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, वहीं दो बार शासन द्वारा वर्षा गढ़ेकर की नियुक्ति अध्यक्ष पद पर की गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नीतू परमार के पक्ष में आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतू परमार ने यह लंबी लड़ाई कांग्रेस के समर्थन से जीती, लेकिन अंततः भाजपा ने उन्हें पुनः पार्टी में शामिल कर अंतिम राजनीतिक जीत हासिल कर ली। अब इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के उन कार्यकर्ताओं को असमंजस में डाल दिया है, जो बीते वर्षों में अपने-अपने नेताओं के समर्थन में एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाते रहे थे। फिलहाल मुलताई की राजनीति में नीतू परमार की घर वापसी को आने वाले समय के बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

विधायक, जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री रहे मौजूद, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत –मुलताई नपाध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार ने एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लिया है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार तथा भाजपा जिला मंत्री वर्षा गडेकर की मौजूदगी में नपा अध्यक्ष नीतू परमार एवं उनके पति प्रहलाद सिंह परमार भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर दोनों का स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर बधाई दी। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की रीति-नीति, संगठनात्मक कार्यशैली और विकासपरक सोच से प्रभावित होकर लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं।

पीएमजीएसवाय अंतर्गत बैतूल-हरदा को 76.31 करोड़ की सौगात

● केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके के प्रयास से बैतूल–हरदा को मिली 15 सड़कों की सौगात

बैतूल। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाय के अंतर्गत बैतूल-हरदा संसदीय क्षेत्र की 15 महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 76.31 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी तथा कुल 81.51 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण होगा। यह स्वीकृति केंद्रीय राज्यमंत्री व क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके के प्रयासों से मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। स्वीकृत सड़कों में बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र की एनएच-69 के पास साबडी रोड से डोंगरपुर, साबडी से साबडी ढाना तथा खल्ला से खल्ला ढाना मार्ग शामिल हैं। वहीं हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र में बोरपानी से रातामाटी, राजाबरारी से मोहगांव टोला, गोहाटी से पाटियाकुंवा, महुखाल से कयारी, लोढ़ीढाना-कचनार रोड से देबरबंदी, बड़झिरी लाखदेह चुनही रोड से बापचा, बोथी से महूखाल, बडझिरी से लखादेह, बडझिरी लखादेह से चूर्णी, रहटगांव बोरपानी से गांगराढाना, मगरधा बढ़झिरी से बंशीपुरा तथा हरदा-नर्मदापुरम रोड से पिपल्याकला मार्ग को स्वीकृति मिली है।

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। किसानों को कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की पहुंच मजबूत होगी। केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण मध्यप्रदेश सहित बैतूल-हरदा संसदीय क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारियों को मिला भूतपूर्व सैनिक का दर्जा

बैतूल । भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस के अधिकारियों को आधिकारिक रूप से भूतपूर्व सैनिक ईएसएम का दर्जा बहाल कर दिया गया है ।अब एमएनएस अधिकारी भी थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना के अन्य कर्मियों के समान सभी ईएसएम लाभों के लिए पात्र होंगे । जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बैतूल कैप्टन आईएन सुमित सिंह ने बताया कि जिला बैतूल के समस्त सेवानिवृत्त सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी अपना पंजीयन कराने के लिए जिला सैनिक कार्यालय बैतूल में संपर्क कर सकते है ।

शहर की व्यवस्थाएं सुधारने मैदान में उतरे नपा सीएमओ

भाजपा प्रदेश, बैतूल विधायक के निर्देश पर शहर में चला निरीक्षण अभियान

बैतूल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक के निर्देशानुसार नगर सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवनीत पांडे ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधाओं, जर्जर भवनों और नगरपालिका संपत्तियों की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। सीएमओ नवनीत पांडे ने सबसे पहले लल्ली चौक स्थित रोटरी का निरीक्षण किया, जहां रोटरी के अव्यवस्थित निर्माण और गलत अलाइनमेंट की स्थिति सामने आई। इस पर इंजीनियरिंग और ट्रैफिक विभाग को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। वहीं हाईमास्ट पोल के आसपास अतिक्रमण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए।

4 दिन की खुदाई से ही सूखी पहाड़ी पर फिर फूटा पानी

● भोपाल के पास बेतवा उद्गम क्षेत्र में मिला 'पार्वती कुंड'; सफाई करते ही भरने लगा जल

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पास ग्राम झिरी स्थित बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के लिए 10 मई से शुरू हुए श्रमदान अभियान के चौथे दिन बुधवार को श्रमदानियों को पहाड़ी पर एक प्राचीन प्राकृतिक जलस्रोत मिला। इसे 'पार्वती कुंड' नाम दिया गया है। जैसे ही श्रमदानियों ने मिट्टी और पत्थर हटाकर कुंड की सफाई शुरू की, अंदर से पानी की झिर फूट पड़ी। देखते ही देखते वर्षों से सूखा पड़ा कुंड पानी से भरने लगा। वहां मौजूद लोगों ने इसे किसी चमत्कार जैसा बताया। करीब 3 घंटे तक लगातार हाथों से खुदाई कर छह फीट गहरे और सात फीट चौड़े कुंड को फिर जीवित किया गया। बाद में तीन किलोमीटर दूर से फावड़ा और तगाड़ी मंगवाई गई। इसके बाद पास का दूसरा छोटा कुंड भी पानी छोड़ने लगा।

सूखी पहाड़ी पर ऐसे फूटा पानी – अभियान से जुड़े लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे-जैसे मिट्टी हटती है, कुंड के भीतर से पानी रिसना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में कुंड का तल पानी से भर जाता है और वहां मौजूद श्रमदानी खुशी से झूम उठते हैं।

जैसे वर्षों से पानी बाहर आने का इंतजार कर रहा था – मप्रविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े विशेषज्ञों ने मौके पर जलधारा की संरचना का अध्ययन भी किया। उनका कहना है कि यह प्राकृतिक जलस्रोत लंबे समय से मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गया था। सफाई और जलनिकासी मार्ग खुलते ही पानी फिर सतह पर आ गया।श्रमदानियों का कहना है कि कुंड के आसपास जैव विविधता के संकेत भी मिले हैं। उनका मानना है कि बारिश के मौसम में यह जलस्रोत आसपास के वन्यजीवों के लिए भी सहारा बन सकता है।

4 दिन से लगातार चल रहा श्रमदान – बेतवा उद्गम क्षेत्र के झिरी इलाके में 10 मई से श्रमदान सप्ताह चल रहा है। हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग पहाड़ी क्षेत्र में चेक डैम बना रहे हैं और पुराने जलस्रोतों की सफाई कर रहे हैं। अब तक पांच नए चेक डैम बनाए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल बने कई चेक डैम की मरम्मत भी की गई है। इस अभियान में भोपाल, विदिशा और इंदौर से आए पर्यावरण प्रेमी, वैज्ञानिक, पूर्व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। उद्गम क्षेत्र के पुजारी गोपाल दास ने भावुक होकर श्रमदानियों की तुलना भगीरथ से की। उनका कहना था कि जो कुंड कई वर्षों से पूरी तरह सूख चुका था, उसमें फिर पानी देखना किसी तपस्या के फल जैसा है। श्रमदान अभियान 16 मई तक जारी रहेगा। आयोजकों का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक कुंड भरना नहीं, बल्कि बेतवा नदी के उद्गम क्षेत्र को फिर से जीवित करना है।

शॉर्ट न्यूज

सफलता की कहानी श्री चिराग गौर की जुबानी

विदिशा (निप्र)। श्री चिराग गौर ने बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग में भोपाल के कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है लेकिन पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि कंप्यूटर और तकनीकी क्षेत्र की ओर बढ़ी, इसलिए उन्होंने मेहनत करके सीडीएसी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सीडीएसी एसीटीएस पुणे से कंप्यूटर क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोर्स पूरा होने के बाद जब प्लेसमेंट का समय आया, तब कई कंपनियों से उचित अवसर नहीं मिला मेरी ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में है जबकि उनकी विशेषज्ञता कंप्यूटर क्षेत्र में है। इसी कारण उन्हें कंपनियां अपेक्षित वेतन देने के लिए तैयार नहीं थी। यह समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी दौरान श्री चिराग गौर के चाचा श्री प्रियंक गौर (प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार) शासकीय आईटीआई लटेरी विदिशा ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और आईटीआई में मैकेनिक डीज़ल ट्रेड से एक वर्षीय प्रशिक्षण करने की सलाह दी फिर उन्होंने समर्पण के साथ आईटीआई का प्रशिक्षण 2024-2025 में पूरा किया। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण अधिकारी श्री शिवपाल उइके मैकेनिक डीजल द्वारा तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया तथा मेरे आत्मविश्वास भी बढ़ाया। इसके बाद मैंने सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी जिला सीहोर में अप्रेंटिसशिप हेतु परीक्षा दी और अपने प्रयासों के बल पर परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान मैं श्री चिराग गौर बुधनी प्लांट में अप्रेंटिस के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा संघर्ष, धैर्य और निरंतर सीखने की प्रेरणा देती है। उन्होंने यह सीखा कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, यदि व्यक्ति मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहे, तो सफलता अवश्य मिलती है।

आवारा पशुओं के प्रबंधन और दुर्घटनाओं के समाधान हेतु बैठक संपन्न

रायसेन (निप्र)। जिले में आवारा श्वान एवं आवारा पशुओं के प्रबंधन और दुर्घटनाओं/समस्याओं के समाधान हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आज 11 मई 2026 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कि गई। बैठक में समिति द्वारा जिले में आवारा पशुओं के प्रबंधन और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं/समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पशुपालकों से अपील की गई अपने पशुओं को रोड एवं सार्वजनिक मार्ग पर ना छोड़े, उन्हे सुरक्षित स्थान में रखे, जिससे दुर्घटनाएं एवं आदि समस्याएं नही होगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री कमल सोलंकी, एडीएम श्री मनोज उपाध्याय, समिति के सदस्य एवं सदस्य सचिव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आर्थिक मदद जारी

विदिशा (निप्र)। विदिशा उपखण्ड अधिकारी के द्वारा आरबीसी के एक प्रकरण में मृतक के परिजन को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि ग्राम अहमदानगर नाले में डूबने से दीपक अहिरवार की मृत्यु हो जाने पर मृतक के पिता श्री नथन सिंह अहिरवार पुत्र नारायण सिंह अहिरवार निवासी अहमदानगर को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता आरबीसी 6(4) के प्रावधानो तहत जारी की गई है।

कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 53 प्रगणक व सुपरवाइजर को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री अंशुल गुप्ता ने आज जनगणना-2027 अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 51 प्रगणक व दो सुपरवाइजर को प्रमाण पत्र प्रदाय कर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय विकास एवं प्रगति में समर्पण, कर्तव्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी प्रगणकों व सुपरवाइजर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। हमारी जनगणना हमारा विकास अंतर्गत जनगणना 2027 में विदिशा जिले में सुव्यवस्थित रूप से कार्य जारी है। इस कार्य में विदिशा से जिले में 51 प्रगणक व 02 सुपरवाइजर द्वारा अपने क्षेत्र में जनगणना के मकान सूचीकरण व भवनों की गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उन्हें आज कलेक्ट्रेट स्थित कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने अपने चेंबर में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। जिन प्रगणकों व सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया है उनमें विदिशा और लटेरी तहसील के 09 प्रगणक के अलावा सिरोंज, कुरवाई, बासौदा और शमशाबाद के 6-6 प्रगणक, गुलाबगंज तहसील के 03 प्रगणक और पठारी और त्यौंदा तहसील के तीन-तीन प्रगणक और एक-एक सुपरवाइजर शामिल हैं।

प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने नवविवाहित दंपत्ति को दिया आशीर्वाद

विदिशा (निप्र)। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल ने आज विदिशा जिले के संक्षिप्त प्रवास दौरान श्री महेश श्रीवास्तव के पुत्र एवं श्री प्रियंक श्रीवास्तव के अनुज चिरंजीव मयंक श्रीवास्तव के विवाह उपरांत उनके निवास स्थल शंकरनगर कालोनी में पहुंचकर नवविवाहित दंपत्ति को शुभाशीष एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं प्रदान कीं। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने परिवारजनों से आत्मीय भेंट कर सामाजिक सौहार्द एवं पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया।

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागीय कार्यो तथा सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा कर दिए दिशा-निर्देश

सभी पंचायतें पांचवे वित्त आयोग की राशि से करे विश्राम घाटों का रख रखाव: कलेक्टर

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों तथा योजनाओं की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार और अधिकारीवार सीएम हेल्पलाईन निराकरण की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संतुष्टिपूर्ण निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार सभी अधिकारियों को पोर्टल पर इंट्री करने को कहा। बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करे। उन्होंने तीन माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को शून्य करने का प्रयास करे। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10 बजे जूम मिटिंग के द्वारा समीक्षा भी कि जाएगी। इसके साथ ही राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसी प्रकार सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट और जन आंकाक्षा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का भी गंभीरतापूर्वक निराकरण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गेहूँ उपार्जन के कार्यो की समीक्षा के दौरान परिवहन के कार्य मे तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री और सहकारिता की कालातीत वसूली कराने और भू-अभिलेख का डिजिटलाइजेशन कराने को कहा। उन्होंने पंचायतों में पांचवे वित्त आयोग की राशि से विश्राम घाटों का रख रखाव कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने लोक सेवा गांरटी पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण कर समय सीमा में लाभ प्रदान करे।

प्राथमिकता वाला कार्य है तथा इसकी नियमित मॉनीटरिंग की जाती है। इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोक सेवा गारंटी संबंधी आवेदनों का समयावधि में निराकरण हो। उन्होंने समय सीमा वाले शासकीय पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने, उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समय से जबावदावा दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने जनगणना-2027 के कार्य में नक्शा संबंधी कार्य को पूर्ण कराकर सभी एसडीएम को फाइनल मैप तैयार कर चार्ज अधिकारी को सौंपने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर डिस्पोजल तथा जीरो पेंडेंसी वाले विकासखण्ड स्तरीय टीम को आगामी 15 अगस्त कार्यक्रम पर प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही सभी एसडीएम से विकासखण्ड स्तर पर पेयजल समस्या संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु गठित कंट्रोल रूम के संचालन तथा पेयजल संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर गंभीरता से उसका निराकरण करने को कहा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा दौरान कहा कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व से ही सभी विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था ठीक कराने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही ऐसे जर्जर भवनों है तो उनकी मरम्मत कराएं। अगर भवन खराब अवस्था में है तो नए भवन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करवाएं। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अप्रैल माह की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही 50 दिवस से अधिक समयावधि की शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, खनिज विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, सहायक कलेक्टर श्री अंकित जैन तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे।

मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की व्यवस्थित नीलामी हेतु टोकन व्यवस्था प्रारंभ

विदिशा (निप्र)। कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा द्वारा किसानों की सुविधा एवं मंडी परिसर में सुव्यवस्थित नीलामी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन पहल की गई है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार एवं भारसाधक पदाधिकारी श्री क्षितिज शर्मा तथा कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा श्रीमती नीलकमल वैघ के मार्गदर्शन में सोमवार 11 मई से नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर में कृषि उपज लेकर आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं अन्य वाहनों के लिए टोकन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत मंडी में नीलामी हेतु प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन को मुख्य द्वार से टोकन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद ही वाहन को नीलामी हेतु आरक्षित शेड में खड़ा किया जा सकेगा। मंडी समिति द्वारा इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पहले ही दिन लगभग 700 टोकन जारी किए गए।

मंडी समिति ने बताया कि टोकन व्यवस्था लागू होने से मंडी परिसर में वाहनों की अनावश्यक भीड़ कम होगी, किसानों को अपनी उपज की नीलामी में सुविधा मिलेगी तथा व्यवस्थाएं अधिक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बन सकेंगी। इससे किसानों को समय की बचत के साथ-साथ बेहतर प्रबंधन का लाभ भी प्राप्त होगा। मंडी प्रशासन ने कृषक बंधुओं से अपील की है कि वे मंडी में प्रवेश करते समय अनिवार्य रूप से टोकन प्राप्त करें तथा निर्धारित स्थान पर ही अपने वाहन खड़े करें। साथ ही किसानों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस नई व्यवस्था का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और मंडी प्रबंधन को सहयोग प्रदान करें।

समय सीमा में मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण करने पर तहसील बैतूल नगर की टीम सम्मानित

बैतूल (निप्र)। जनगणना 2026 अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने पर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी बैतूल द्वारा तहसील बैतूल नगर के चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीमती पूनम साहु को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी डॉ सोनवणे ने मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गुणवत्ता एवं समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर अन्य चार्ज अधिकारियों को भी निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा मकान सूचीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सभी अधिकारियों से जनगणना कार्य को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने की अपेक्षा की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, एसडीएम बैतूल डॉ अभिजीत सिंह भी मौजूद रहें।

मरीजों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और अच्छा व्यवहार रखें चिकित्सक

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में सोमवार दोपहर जिला चिकित्सालय के मीटिंग हॉल में स्वास्थ्य सेवाओं एवं अस्पताल व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया तथा उनसे दैनिक कार्यों में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सुबह निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए चिकित्सकों से उनकी अनुपस्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में मरीज दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने शासन की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अच्छे से प्राप्त हो। चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं हो और मरीज परेशान होता रहे, ऐसी स्थिति दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने जिला चिकित्सालय में रेफर इन एवं रेफर आउट मरीजों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से संभावित कारणों पर चर्चा की। साथ ही चिकित्सकों के रिक्त पदों की जानकारी लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के कार्यदायित्वों को लेकर मेट्रन से चर्चा की गई तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मरीजों के प्रति जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

सांदीपनि विद्यालय नटेरन में एसटीईएम कार्यशाला आयोजित

विद्यार्थियों ने सीखे नवाचार आधारित वैज्ञानिक मॉडल, विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से हुए परिचित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने तथा उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने हेतु जिले में निरंतर नवाचार आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में समर कैंप अंतर्गत सांदीपनि सीएम राइज विद्यालय नटेरन में एसटीईएमआधारित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े विभिन्न नवाचारी प्रोजेक्ट मॉडल तैयार करना सिखाया गया।

साथ ही उनकी कार्यप्रणाली को सरल, व्यवहारिक एवं रोचक तरीके से विस्तारपूर्वक समझाया गया। विद्यार्थियों को कक्षा उपस्थिति चार्ट, स्मार्ट डस्टबिन, मीड चार्ट, विद्युत उत्पादन की विभिन्न विधियों, पौधों की स्वचालित सिंचाई प्रणाली तथा सिंचाई पूर्ण होने पर स्वतः पानी बंद होने वाले मॉडल जैसी उपयोगी वैज्ञानिक अवधारणाओं की जानकारी दी गई। पावन सेवा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग, नवाचार आधारित तकनीकों एवं आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं से परिचित कराया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच, रचनात्मकता एवं तकनीकी समझ विकसित करना तथा विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना रहा।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह संदेश भी दिया गया कि विज्ञान केवल पुस्तकीय विषय नहीं, बल्कि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक उपयोगी एवं रोचक क्षेत्र है। कार्यशाला में प्रदर्शित मॉडल विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध हुए। इस एसटीईएम कार्यशाला से विद्यार्थियों को भविष्य में विज्ञान प्रदर्शनी हेतु नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करने में सहायता मिलेगी। समर कैंप अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक साबित हो रही है। जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विज्ञान के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित की गई है।

नगर पालिका अमले ने किया अमृत योजना के कार्यों का निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नगरपालिका पिपरिया के अमले द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में अमृत योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पार्क एवं एमआरएफ सेंटर (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) तथा कंपोस्टिंग यूनिट स्थल का अवलोकन कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया गया। निरीक्षण दल द्वारा अमृत योजना अंतर्गत निर्माणाधीन वाटर बॉडी एवं जल प्रदाय योजना के तहत बनाए जा रहे ओएचटी (ओवरहेड टैंक) स्थल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने तथा गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

ज्ञान भारतम् ऐप के माध्यम से जिले की ऐतिहासिक धरोहरों के डिजिटलीकरण हेतु बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। 'ज्ञान भारतम्' अभियान के अंतर्गत जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण को लेकर संयुक्त कलेक्टर श्री जमील खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं सांस्कृतिक विरासत को 'ज्ञान भारतम्' ऐप के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना एवं आमजन तक उनकी जानकारी उपलब्ध कराना रहा। बैठक के दौरान 'ज्ञान भारतम्' ऐप की कार्यप्रणाली, उसके उद्देश्यों एवं जिले में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा यह विचार रखा गया कि जिले में मौजूद ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके।

इस अवसर पर श्री गणेश लाल जैन द्वारा सीहोर स्थित जैन मंदिरों में संरक्षित प्राचीन पांडुलिपियों, धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि इन पांडुलिपियों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, जिनका संरक्षण एवं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाना आवश्यक है। बैठक में इस विषय पर मंदिर समिति से चर्चा कर इन पांडुलिपियों एवं दस्तावेजों को 'ज्ञान भारतम्' ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करने एवं उनका डिजिटलीकरण करने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि जिले के अन्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी भी चरणबद्ध तरीके से ऐप पर अपलोड की जाएगी। उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों ने कहा कि 'ज्ञान भारतम्' अभियान के माध्यम से जिले की विरासत को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने का यह प्रयास न केवल शोध एवं अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि आमजन को भी अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान एवं इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राइट क्लिक

असल 'लीक' तो नैतिक ईमानदारी और ऑन लाइन व्यवस्था में है...

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

देश भर के 407 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की स्नातक कक्षाओं (यूजी) 1 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) द्वारा विगत 3 मई को आयोजित नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट) 2026 परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद इस में जहां लाखों परीक्षार्थियों में भारी गुस्सा है, वहीं आयोजक संस्था की साख पर फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। असली सवाल तो यही है कि इतनी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं की गोपनीयता आखिर कायम क्यों नहीं रह पाती? एनटीए अपनी स्थापना के 9 साल बाद भी इन लूप होल्स को बंद क्यों नहीं कर पाई? क्या इस धांधली के जारी रहने देने में खुद एनटीए का ही कोई स्वार्थ है अथवा इसके नियंताओं में उसे रोकने की क्षमता ही नहीं है? नीट जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा के रद्द होने का मुद्दा अब प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक भी बन गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीट रद्द। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया।

परीक्षाएं पहले भी इस देश में होती रही हैं, लेकिन उनकी अपनी पवित्रता, गोपनीयता और सत्यनिष्ठा होती थी। अपवाद स्वरूप ही किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र 'लीक' होने जैसी घटना होती थी, जबकि तब लगभग सारा मनुष्यों द्वारा ही किया जाता था। आज अधिकांश काम तकनीक आधारित है, लेकिन पवित्रता और गोपनीयता का पैमाना रसातल को चला गया है। आए दिन पेपर लीक होने, पेपर सेटिंग में धांधली होने, परीक्षा अगर ठीक से हो भी गई तो रिजल्ट में भी गड़बड़ी जैसी शिकायतें आम होती जा रही हैं। इसके पीछे असल कारण परीक्षा के प्रति बुनियादी ईमानदारी का अभाव और पवित्रता के नैतिक आग्रह का रसातल में जाना और ऑन लाइन जैसी तकनीकी पद्धतियां भी हैं, जिनसे काम की गति और व्यापकता भले बढ़ी हो, लेकिन पारदर्शिता न्यूनतम हो गई है। कोई किसी भी साइट को हैक कर सकता है तो कोई भी पेपर किसी भी स्तर पर लीक हो सकता है। कुछ जगह तो खुद पेपर सेंटर ही धंधा करते पाए गए हैं तो कई स्थानों पर प्रिंटिंग प्रेस के लोग ही पैसे की खातिर अपना ईमान बेचने में संकोच नहीं कर रहे हैं। यह अत्यंत शर्मनाक और चिंतनीय स्थिति है। क्योंकि हमारी प्रवेश परीक्षाओं की इस बदहाली और गिरती साख का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। और इसकी वजह से जो परीक्षार्थी ईमानदारी से परीक्षा पास करते हैं, उनकी योग्यता को भी संदेह से देखा जाता है। हालांकि योग्यता और मेहनत को पलीता लगाने वाले इस अवैध कारोबार में जो लोग लगे हैं, उन्हें नैतिक मूल्यों की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। कई जगह तो उन्हें किसी न किसी स्तर पर राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। जिस तरह हमारे यहां 'पेपर लीक' एक संगठित कारोबार बन चुका है, वैसा तो छोटे- छोटे देशों में भी नहीं होता। उच्च शिक्षा की अपनी एक पवित्रता और प्रामाणिकता होती है। हमारे देश में यही नीलाम हो रही है।

इस बीच पेपर लीक होने की घटना से परेशान नीट ने प्रवेश परीक्षा ही रद्दकर इसे पुनः आयोजित करने की घोषणा की है। साथ ही इस पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने आरंभिक जांच में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आगे और भी खुलासे होंगे। सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, चोरी और सबूत नष्ट करने जैसी भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) अधिनियम-2024 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। भारत में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024) के तहत किसी परीक्षा का पेपर लीक करने पर अपराधी को 3 से 5 साल तक की जेल तथा 10 लाख रू. तक जुर्माना और पेपर लीक का संगठित अपराध करने पर 5 से 10 साल की जेल तथा 1 करोड़ रू. जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जिस तरह पेपर लीक गिरोहों के हौसले बुलंद हैं, उससे लगता है कि उन्हें कहीं ऊंचे स्तर पर भी संरक्षण प्राप्त है और कानून का कोई खौफ नहीं है। कायदे से तो पेपर लीक को एक अत्यंत गंभीर नैतिक अपराध और देशद्रोह माना जाना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि कोई भी पेपर किस स्तर पर लीक होता है और ऐसा न हो सके इसे रोकने के क्या तकनीकी, कानूनी और नैतिक उपाय हैं, इस बारे में बहुत स्पष्ट और विश्वसनीय उपाय और जानकारी नहीं है। वैसे भी भारत में साइबर सुरक्षा की हालत दयनीय ही है।

नीट परीक्षा में बैठने वाले लाखों बच्चे ऐसे हैं, जिनके अभिभावकों ने भारी पैसा खर्च कर बच्चे को डॉक्टर बनाने का सुनहरा सपना देखा था। लेकिन परीक्षा के दिन के कुछ समय पहले ही देश में कई जगह इसके गैस पेपर वायरल हुए, जो वास्तविक पेपर से काफी मिलते जुलते थे। ये पेपर कई परीक्षार्थियों ने लाखों रूपए देकर खरीदे थे, बिना यह सोचे कि अगर परीक्षा रद्द हो गई तो उनका यह पैसा पानी में चला जाएगा। उधर पेपर लीक को लेकर एनटीए ने अपने बयान में कहा कि जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह तय हुआ कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखें और नए एडमिट कार्ड का शेड्यूल आने वाले दिनों में एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से जारी किया जाएगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा परीक्षा के पेपर में भी गोपनीयता बरकरार रह पाएगी या नहीं।

दुर्भाग्य से इस पेपर लीक मामले के तार अन्य राज्यों के गिरोह के साथ मप्र के सीहोर से जुड़ रहे हैं, जहां पुलिस ने पेपर लीक मास्टर माइंड शुभम् खैरनार को नाशिक से गिरफ्तार किया। शुभम वहां की सत्यसाई यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जाता है, जो कभी कॉलेज नहीं गया। शुभम के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसका खुलासा होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा की विश्वनसनीयता और पारदर्शिता शुरू से सवालों के घेरे में रही है। एनटीए का गठन भारत सरकार ने देश भर में होने वाले प्रमुख कॉलेज और स्कूल प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी की अलग-अलग शिकायतों के बाद 2017 में समूची प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीयता बनाने के उद्देश्य से किया था। एनटीए आज देश में हर साल मेडिकल सहित विभिन्न विषयों सम्बंधित कॉलेजों में प्रवेश की केन्द्रीय स्तर पर 21 तथा 4 स्कूलों की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। इनमें भी सर्वाधिक विवादित नीट यूजी और पीजी की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाली कमाई। माना जाता है कि व्यक्ति एक बार डॉक्टर बन जाए तो फिर सब कुछ हरा ही हरा है। यही कारण है कि लोग नीट परीक्षा का पेपर पहले हासिल करने के लिए लाखों रू. खर्च करने को तैयार हैं। बस एक बार किसी तरह एडमिशन मिल जाए। अगर इसी साल की नीट यूजी की बात की जाए तो इसमें करीब 22 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। यदि इनमें से 1 प्रतिशत परीक्षार्थियों को भी लीक पेपर या गैस पेपर मिले होंगे और उन्होंने औसतन 10 लाख रू. प्रति पेपर भी खर्च किए होंगे तो यह अवैध कारोबार लगभग 220 करोड़ का होता है। जबकि एनटीए को परीक्षा शुल्क में (अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग फीस है) प्रति परीक्षार्थी औसतन 1 हजार रू. मान लें तो उसे 220 करोड़ रू. की आय हुई होगी। यानी मोटे तौर पर यह आय पेपर लीक कारोबार के बराबर ही बैठती है।

उल्लेखनीय है कि एनटीए का काम पहले भी बहुत विश्वसनीय नहीं रहा है। 2024 में भी एजेंसी को तब भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब असामान्य रूप से बहुत ज्यादा उम्मीदवारों ने रैंक 1 हासिल की थी। उस समय ग्रेस मार्क्स, बढ़े हुए स्कोर और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए थे। तब भी पेपर लीक और संगठित नकल के आरोप सामने आने के बाद जांच शुरू की गई थी। कई लोगों को राज्य पुलिस एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया था। छात्र, अभिभावक और शिक्षक परीक्षा रद्द कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने माना था कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की 'पवित्रता' प्रभावित हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने एनटीए के कामकाज में सुधार की घोषणा की थी। लेकिन नतीजा सामने है।

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका

पनामा पेपर लीक मामले में लिया था शिवराज के बेटे का नाम

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। झाबुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक मामले का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लेते हुए उनकी तुलना पाकिस्तान के नवाज शरीफ से की थी। राहुल गांधी के इसी बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय चौहान ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था।

हाई कोर्ट में आज क्या हुआ- सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने अपना जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए दो दिन का समय दिया है। राहुल गांधी के वकीलों ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया।

सिर्फ सात गाड़ियों के काफिले में निकले सीएम

डिप्टी सीएम ने घटाए वाहन, मंत्री एक कार से घूमे

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील के बाद एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले में से 6 वाहन कम कर दिए हैं। सीएम के कारकेड में अब तक 13 वाहन चलते थे अब 7 वाहन ही साथ रहेंगे। भोपाल से नरसिंहपुर रवाना होते वक्त सीएम डॉ. मोहन यादव के काफिले में आज सिर्फ सात वाहन ही नजर आए।

डिप्टी सीएम शुक्ल का ऐलान कम से कम गाड़ियां काफिले में रहेंगी- सीएम के बाद अब डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने अपने काफिले में कम से कम गाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने सोशल मीडिया पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रहित में ईंधन संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ योगदान देगा। आगामी आदेश तक विभागीय भ्रमण, निरीक्षण एवं अन्य शासकीय गतिविधियों में न्यूनतम वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अनावश्यक वाहन रैली, अतिरिक्त काफिले और ईंधन की खपत वाले आयोजनों से परहेज किया जाए।

विभाग के अफसर कार पुलिंग को प्राथमिकता दें

डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी भी शासकीय कार्यों में सादगी अपनाते हुए सार्वजनिक परिवहन अथवा साझा वाहन व्यवस्था को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भोजन का भी सीधा संबंध है। इसी दृष्टि से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे रासायनिक उर्वरकों (जो अधिकांश आयातित होते हैं) का उपयोग कम हो, भूमि और जल की गुणवत्ता सुरक्षित रहे तथा आमजन को स्वास्थ्य कर अन्न उपलब्ध हो।

यह जनस्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि ऊर्जा संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण के इस संदेश को भी जनजागरूकता अभियानों में शामिल करें। ईंधन की बचत, स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक कृषि, ये सभी स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के आधार हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। प्रत्येक छोटी बचत, देश की बड़ी शक्ति बनती है।

- **अपील का असर- उज्जैन में सिंहस्थ कार्यों के निरीक्षण के लिए ट्रैवलर बस से पहुंचे अधिकारी,6750 का सफर 250 में-** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद उज्जैन जिला प्रशासन ने भी पेट्रोल-डीजल बचाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। बुधवार से सिंहस्थ कार्यों के निरीक्षण के लिए अधिकारी अलग-अलग वाहनों की बजाय एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बुधवार सुबह संभागायुक्त और सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष

मिश्र, यूडीए सीईओ संदीप सोनी, तहसीलदार आलोक चोरे, जल संसाधन विभाग के ईई मयंक सिंह, योगेश बिरला, अवनेंद्र सिंह, ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार सहित 15 अधिकारी एक साथ अर्बेनिया वाहन में बैठकर सिंहस्थ मेले के लिए बनाए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। सिंहस्थ के कार्यों का पिछले एक सप्ताह से अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। रोज कमिश्नर, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी अलग-अलग 15 वाहनों से पहुंचते थे। वे करीब 16 किमी का सफर करते हैं।

मंत्री विश्वास सारंग ने छोड़ा गाड़ियों का काफिला, एक गाड़ी से गए मंत्रालय

पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की अपील का असर अब दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने काफिला छोड़ने का निर्णय लिया है। उनके साथ अब गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा। वह आज मंत्रालय एक गाड़ी से गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अह्वान अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हैं। इस देश के लिए यदि हम कुछ करना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह को स्वीकार करें। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कम से कम पेट्रोल-डीजल का उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस देश को खड़ा करने का काम किया है।

संविधान के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सतत संवाद आवश्यक : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के मीडिया प्रबंधन विभाग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा तैयार विशेष पत्रिका कंस्टीट्यूशन टू कम्यूनिकेशन का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना

करते हुए कहा कि संविधान के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रभावी संवाद एवं जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण संस्थान बताते हुए कहा कि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी मीडिया, आईटी, फाइनेंस और बिजनेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे विषयों पर निरंतर रिसर्च और बौद्धिक विमर्श को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे भविष्य में सकारात्मक और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकें।

यह पत्रिका मीडिया लॉ एंड एथिक्स पर आधारित है, जिसमें पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के साथ-साथ मीडिया कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पत्रिका का निर्माण विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. विजय मनोहर तिवारी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश वाजपेई जी के विशेष मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

सभी नागरिक क्यूआर कोड स्केन कर स्वच्छता सर्वेक्षण फीडबैक में करें सहभागिता : आयुक्त भोंडवे

म.प्र. में नागरिकों ने सर्वेक्षण में दर्ज कराए 19 लाख से अधिक फीडबैक

भोपाल (नप्र)। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश अपनी संकल्पबद्धता और जन-सहयोग के अनूठे संगम के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के कुल 406 नगरीय निकायों में स्वच्छता के प्रति जो उत्साह और चेतना जाग्रत हुई है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नागरिकों द्वारा अब तक दर्ज कराए गए 19 लाख से अधिक फीडबैक हैं। यह संख्या न केवल नागरिकों की अपनी शहर की स्वच्छता के प्रति सजगता को दर्शाती है, बल्कि यह प्रदेश की उस सामूहिकता का भी परिचायक है जो मध्यप्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर बनाए रखने के लिए तत्पर है। विभाग द्वारा इस विशाल जन-समर्थन को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो आगामी रैंकिंग में प्रदेश के शहरों की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दिये गये क्यूआर कोड को स्केन कर स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में अपना फीडबैक दर्ज करे।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के सर्वेक्षण की सबसे अभिनव और क्रांतिकारी विशेषता इसकी मूल्यांकन प्रणाली में किया गया मूलभूत परिवर्तन है, जिसमें नागरिक फीडबैक और जन-शिकायत निवारण (ग्रीवांस रिड्रेसल) को मुख्य आधार बनाया गया है। पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों की तुलना में इस बार रैंकिंग की गणना में नागरिकों की प्रतिक्रिया और उनकी शिकायतों के त्वरित व प्रभावी समाधान को अत्यधिक महत्व और वेटेज प्रदान किया गया है। इससे स्वच्छता के प्रबंधन को केवल प्रशासनिक सक्रियता तक सीमित न रखकर इसे पूर्णतः नागरिक-केंद्रित बनाना है। अब शहरों की सफलता का पैमाना केवल कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि धरातल पर नागरिकों का संतुष्टि स्तर और उनकी समस्याओं के निराकरण की गतिशीलता होगी। मध्यप्रदेश के 406 नगरों में नवीन व्यवस्था के अनुरूप कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन और दृश्य स्वच्छता के साथ नागरिक संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग का निरंतर प्रयास है कि स्वच्छता के इस महाभियान में तकनीक और पारदर्शिता का समावेश कर हर नागरिक को इस प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा बनाया जाए।

बच्चों का सर्वांगीण विकास ही विकसित मप्र @2047 की आधारशिला : मंत्री भूरिया

भोपाल (नप्र)। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश के बच्चों का सर्वांगीण विकास ही राज्य के सतत और समावेशी विकास की आधारशिला बनेगी। मंत्री सुश्री भूरिया बुधवार को होटल कोर्टयार्ड मैरियट में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'चाइल्ड बजटिंग इन मप्र' विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।

बजट 2026-27: बच्चों के लिए रिकॉर्ड आवंटन- मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दिखती है।

उन्होंने मुख्य वित्तीय प्रावधानों को साझा करते हुए कहा कि बजट में इस वर्ष 26 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में 23 हजार 747 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें पोषण 2.0 जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। राज्य के कुल व्यय का 13.7 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर व्यय के लिये आवंटित किया गया है।

19 विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता- मंत्री सुश्री भूरिया ने स्पष्ट किया कि बच्चों का विकास केवल संबंधित बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा चाइल्ड बजट स्टेटमेंट में अब 19 विभागों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय जैसे सभी विभागों को एक निर्धारित लक्ष्य अनुसार मिलकर काम करना होगा। विभागों के बीच जब बेहतर समन्वय होगा, तभी बजट का वास्तविक लाभ धरातल पर दिखेगा।

5 वर्षों की सफलता और 'इक्विटी' पर जोरः विलियम हैनलोन जूनियर

यूनिसेफ मध्यप्रदेश के चीफ फील्ड स्टॉफ, श्री विलियम हैनलोन ने कहा कि मध्यप्रदेश 'चाइल्ड बजटिंग' के 5 सफल वर्ष पूरे कर चुका है और यह केवल खर्च की रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर 'परिणाम-आधारित' बजटिंग की ओर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश की अधिकांश जनजातीय आबादी को देखते हुए बजट में लिंग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

विकसित भारत @2047 के लिए रणनीतिक निवेश: यूनिसेफ की सोशल पॉलिसी चीफ (दिल्ली) सुश्री क्रिस्टीना पोपीवानोवा ने मध्यप्रदेश की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुरूप बताया।उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बच्चों में निवेश को लाभार्थी के नजरिए से नहीं बल्कि उत्पादकता के आधार पर देखा जाए। महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री अभिताभ अवस्थी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बाल बजट के अंतर्गत 75 हजार 587 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के कुल बजट का 19.4 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत है। वर्ष 2022 में बाल बजटिंग की पहल शुरू करने के बाद, मध्यप्रदेश अब इसके पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है।